हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 235 बेमेतरा, सोमवार 20 अप्रैल 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

सीएम स्टालिन ने दुख जताया

तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री में धमाका 18 की मौत,कई घायल

नई दिल्ली/ एजेंसी

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के पास कट्टानारपट्टी स्थित 'वनजा पटाखा फैक्ट्री' में रविवार को धमाके से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताया है। विरुधुनगर, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के पास कट्टानारपट्टी स्थित 'वनजा पटाखा फैक्ट्री' में रविवार को धमाके से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विरुधुनगर जिले में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में कई लोगों की मृत्यु की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने का अनुरोध किया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता समन्वय करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस फैक्ट्री का मालिकाना हक गोविंदनाल्लूर निवासी मुथु मानिकम के पास है और यह एक वैध आरडीओ लाइसेंस के तहत संचालित हो रही थी।

फैक्ट्री परिसर में 30 से अधिक कमरे बने हुए हैं और यहां 50 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। रविवार को जब लगभग 30 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके से फैक्ट्री के कम से कम चार कमरों को भारी नुकसान पहुंचा और देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक नुकसान काफी गंभीर हो चुका था। हादसे के समय फैक्ट्री में 30 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी रखी। अब तक लगभग 18 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्रीनाथ स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं।

सीएम एमके स्टालिन ने जताया दुख

इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और उन्हें इससे गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। साथ ही प्रशासन को राहत और सहायता कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने का अनुरोध किया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता समन्वय करने का निर्देश दिया है।

संक्षिप्त समाचार

पुणे हवाई अड्डे पर वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग, 11 घंटे बंद रहा रनवे

पुणे। पुणे के हवाई अड्डे पर बीती रात भारतीय वायुसेना के एक विमान को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। बताया जा रहा रात करीब 10ः25 बजे वायुसेना के एक विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। इसके चलते विमान को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और वह रनवे पर ही फंस गया। इस वजह से करीब 11 घंटे तक हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन प्रभावित रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्ड लैंडिंग के बाद विमान में आग लगने की छोटी दुर्घटना हुई, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रनवे अवरुद्ध होने के कारण हवाई अड्डे पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अधिकारियों ने विमानों के लिए एक नोटिस जारी किया और कई आने वाली उड़ानों को गोवा, चेन्नई, सूरत, कोयंबटूर और नवी मुंबई की ओर डायवर्ट किया गया। रनवे बंद होने के चलते हवाई अड्डे पर आज सुबह 7.30 बजे तक विमानों का संचालन बंद रहा। हवाई अड्डे के निदेशक के मुताबिक, इस दौरान 5 एयरलाइंस की 91 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें इंडिगो की 65, एयर इंडिया की 6, स्पाइसजेट की 5, अकासा एयर की 5 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 10 उड़ानें शामिल थीं। भारतीय वायु सेना ने कहा कि रनवे को बहाल कर दिया गया है।

दिल्ली समेत 12 राज्यों में अंधड़-बारिश का अलर्ट, पारा 40 डिग्री के पार

नईदिल्ली। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी भीषण होती जा रही है। कई जगह तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश होने के कारण मौसम पलट गया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कई राज्यों में अंधड़ के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 21 अप्रैल तक लू चलने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जब पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर बाद बादल छाने के साथ मौसम बदल गया।

सम्मान' के साथ चाहिए शांति

परमाणु अधिकारों पर झुकने को तैयार नहीं राष्ट्रपति पेजेशकियन..

ईरान/ एजेंसी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर तेहरान का मंशा साफ करते हुए कहा कि उनका देश चल रहे संघर्षों को 'सम्मान के साथ' खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि किसी भी विदेशी शक्ति या देश के पास ईरान को उसके वैध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परमाणु अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। पेजेशकियन के अनुसार, ईरान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है न कि युद्ध का विस्तार करना। उन्होंने स्पष्ट

शब्दों में कहा कि ईरान ने कभी भी किसी संघर्ष की शुरुआत नहीं की है और न ही उसकी योजना किसी दूसरे देश पर हमला करने की है। उन्होंने वैश्विक समुदाय को आश्वस्त किया कि ईरान केवल आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का पालन कर रहा है। राष्ट्रपति ने विरोधियों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक बुनियादी ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाकर अपने लक्ष्यों को पाने में विफलता हासिल की है। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सीधे सवाल उठाए। ईरानी छात्र समाचार एजेंसी के हवाले से उन्होंने पूछा कि किस आधार पर वाशिंगटन ईरान की परमाणु गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता लेकिन वे यह नहीं बताते।

दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सीआर पार्क थाना क्षेत्र के अलकनंदा-तारा अपार्टमेंट में पड़ोसी ने पैसे के लेनदेन के विवाद में चाकू से गोदकर राकेश सूद (60) और उनके बेटे करण सूद (33) की शुक्रवार रात हत्या कर दी। बीचबचाव में राकेश का भतीजा भी घायल हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तारा अपार्टमेंट का रहने वाले आरोपी असद ने पीड़ितों पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पीएस सीआर पार्क थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।

ट्रंप की आखिरी चेतावनी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले....डील मानो,वरना अंधेरे में डूबेगा ईरान

वाशिंगटन/ एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने ईरान को सैन्य तबाही की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मौजूदा समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तो अमेरिका उसके तमाम पावर प्लांट और पुलों को जमींदोज कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज में गोलीबारी कर मौजूदा सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी हमलों का निशाना फ्रांस

और ब्रिटेन के जहाज बने हैं। ट्रंप के मुताबिक, ईरान का यह कदम उसकी हताशा को दर्शाता है। इस तनाव के बीच ट्रंप ने कूटनीतिक रास्ते का आखिरी विकल्प भी खुला रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक दल कल शाम पाकिस्तान की राजधानी इस्लाबाद पहुंच रहा है। वहां ईरान के साथ निर्णायक बातचीत होनी है। ट्रंप ने कहा कि यह ईरान के पास आखिरी मौका है। ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी ने उसे पहले ही बंद कर रखा है। इससे ईरान को रोजाना 50 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जहाज अब तेल और माल लोडिंग के लिए अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का के बंदरगाहों का रुख कर रहे हैं। जिससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है।

महिला आरक्षण पर विपक्ष की सोच कुत्सित

सीएम योगी बोले- पाप धोने का मौका खो दिया

नई दिल्ली। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष की सोच कुत्सित है और इससे किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते समय स्पष्ट किया था कि देश में चार प्रमुख वर्ग हैं महिला, गरीब, युवा और किसान। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवाद की राजनीति करने वाले

कुछ दलों ने अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाया है, और यही कारण है कि वे प्रगतिशील कदमों का विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया गया, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उसका विरोध किया।

कक्षा एक से 10वीं तक मराठी नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

मुंबई। महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा एक से 10वीं तक मराठी भाषा अनिवार्य की गई है. लेकिन जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला सरकार ने किया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत प्रक्रिया तय की है और इस संबंध में एक सरकारी निर्णय (जीआर) जारी किया है। सरकारी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से ही राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी एक अनिवार्य विषय है। यह नियम महाराष्ट्र अनिवार्य शिक्षण और मराठी भाषा अधिगम अधिनियम, 2020 के लागू होने के साथ अनिवार्य किया गया था।

हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी

महिलाओं के लिए मसीहा बनना आसान नहीं है,सरकार की साजिश नाकाम-प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की जो साजिश थी, उसको रोका गया। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी और यह सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर साफ दिख रहा था...मुझे लगता है कि यह एक साज़िश है कि किसी तरह उन्हें सत्ता में बने रहना है... इसलिए इसे हासिल करने के लिए, वे महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं... उन्होंने सोचा कि अगर यह पास हो गया, तो वे जीत जाएंगे। अगर यह पास नहीं हुआ, तो वे दूसरी पार्टियों को महिला विरोधी बताकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे... हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए मसीहा बनना आसान नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। पूरे द्वहृष्ठद्ब अलायंस ने अपना स्टैंड बहुत साफ़ कर दिया है, और इस वोट ने इसे और भी साफ़ कर दिया

है कि, हमारी समझ से, यह बिल जो पेश किया गया था और तीन दिन की चर्चा महिला रिज़र्वेशन के बारे में नहीं थी; यह सिर्फ़ डिलिमिटेशन के बारे में थी, और हम सभी ने इस पर अपने विचार बहुत साफ़ तौर पर बताए हैं। कांग्रेस स्फ्र प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, जिस तरह से वे यह बिल लाए हैं, जो चीज़ें उन्होंने इससे जोड़ी हैं, डिलिमिटेशन, 2011 की जनगणना, यह बहुत साफ़ है कि उन्हें पता था कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा। उन्हें बस पॉलिटिकल क्रेडिट चाहिए था... कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा हम बहुत साफ कह रहे हैं, और हम यह हर प्लेटफॉर्म से कहेंगे, हम यह हर राज्य में कहेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि द्वहृष्ठद्ब गठबंधन की हर पार्टी यह बहुत साफ कहेगी- वह 2023 का कानून लाओ जो पास हुआ था।

पीएम मोदी ने टीएमसी पर लगाया विश्वासघात का आरोप

टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को पारित होने से रोक दिया-पीएम...

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हर जनसभा पहले से ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। मुझे बताया गया कि लोग 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। यह माहौल, यह प्यार, यह उत्साह, यह जोश, यह विरोध भी उस बेरहम सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है।'पीएम मोदी ने आगे कहा, बीजेपी की पहचान महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा है। इसीलिए, देश के हर राज्य में बहनें और बेटियां बीजेपी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद देती हैं। हम एक विकसित भारत के निर्माण में बेटियों की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को राजनीति में भी आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आपने देखा कि संसद में क्या हुआ। टीएमसी ने एक बार फिर बंगाल की बहनों के साथ विश्वासघात किया है। पीएम मोदी ने कहा, 'बंगाल की महिलाएं 33त्न आरक्षण चाहती थीं। मोदी ने इसे सुनिश्चित किया। बंगाल

की महिलाएं चाहती थीं कि इसे 2029 से लागू किया जाए। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किए। लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां स्द्गन्न और एमपी बनें, क्योंकि बंगाल की बेटियां उनके 'महा जंगल राज' को चुनौती दे रही थीं। इसलिए, टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और महिलाओं को 33त्न आरक्षण देने वाले कानून को पारित होने से रोक दिया।' पीएम मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में युवा भर्ती, शिक्षकों की नियुक्ति और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही चक्रवातों से प्रभावित लोगों के लिए आवंटित राहत निधि का भी दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने लोगों को लूटने में पीएचडी कर ली है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं देख रहा हूं कि बंगाल का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार और कार्यकर्ता नहीं... ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता लड़ रही है, बंगाल के मेरे भाई-बहन चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं-यही भाव देख रहा हूं, इसलिए आज टीएमसी के गुंडे डर से कांप रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कह रहा है कि इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही स्वर सुनाई दे रहा है।

ज्ञानेश की बढ़ने वाली है मुसीबत!

महिला आरक्षण बिल के बाद होगा एक और वार

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली सफलता के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। विपक्षी दल उन्हें हटाने के लिए संसद में एक नया नोटिस लाने पर विचार कर रहे हैं। द टाईम्स आफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपसी चर्चा कर रहे हैं और नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब पहले दिया गया नोटिस ओम बिरला और सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा खारिज कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार,

नोटिस खारिज करते समय विस्तृत कारण भी बताए गए थे। विपक्ष का मानना है कि पहले नोटिस में रही कमियों—खासतौर पर 'कदाचार के ठोस उदाहरणों' की कमी—को दूर कर इस बार मजबूत आधार के साथ प्रस्ताव लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फिलहाल यह चर्चा शुरुआती चरण में है।

उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, वित्तीय साक्षरता लैब और कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का किया लोकार्पण

प्रदेश सरकार की सकारात्मक व विकासपरक सोच से जिले में हो रहे नवाचार : साव

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर :-उत्तर बस्तर कांकेर 19 अप्रैल 2026प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर में ट्रामा सेंटर तथा ओपीडी एवं अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा पुत्री शाला परिसर का जीर्णोद्धार कर वित्तीय साक्षरता लैब और कचहरी परिसर स्थित मावा मोदोल कोचिंग संस्थान प्रांगण में कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का भी लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री साव ने किया। आज दोपहर कोया बाना आदिवासी संस्कृति संग्रहालय के लोकार्पण पश्चात आज दोपहर कोया बाना आदिवासी संस्कृति संग्रहालय के लोकार्पण पश्चात नगरवासियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांकेर जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि यहां कुल 11 करोड़ 21 लाख रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों और नवाचारों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सकारात्मक और विकासपरक सोच ही परिणाम है कि जिले में इतनी तादाद में विकास की झलकियां देखने को मिल रही हैं। वहीं आने वाली पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति और विरासत को करीब से जानने के लिए कोया बाना जैसे बहुउद्देशीय संग्रहालय का आज लोकार्पण हुआ। श्री साव ने कहा कि कांकेर जिले को सहेजने और संवारने का काम शासन, प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधि के द्वारा परस्पर समन्वय के साथ किया जा रहा है। उन्होंने नगरवासियों को इन संस्थानों का लाभउठाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि की आसंदी से कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री साव के नेतृत्व में कांकेर जिले को लगातार सौगातें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की इच्छाशक्ति से बस्तर के नक्सलमुक्त होने के बाद अब यहां सतत् विकास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहां की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को संजोने व संवर्धन करने हर संभव प्रयासरत है, जिसका उदाहरण कोया बाना संग्रहालय है जो युवाओं को उनकी प्राचीन परंपरा और सभ्यता से अवगत कराएगा। कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों ने मासिक पत्रिका नवांकुर और हल्बा जनजाति की लोक संस्कृति नामक पुस्तिका का विमोचन किया। विदित हो कि कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान में गोड़ी पाठशाला का संचालन और सांस्कृतिक लाइब्रेरी की स्थापना, आदिवासी पुरातत्व संग्रहालय एवं युवाओं के लिए रेडियो स्टूडियो की स्थापना की गई है। उक्त संस्थान की स्थापना जिला खनिज न्यास निधि मद से 30 लाख रूपए की लागत से की गई है। ट्रामा सेंटर और अतिरिक्त अस्पताल भवन का किया लोकार्पण इसके पहले उप मुख्यमंत्री साव ने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय में आधुनिक तकनीक से लैस ट्रामा सेंटर और ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उक्त ट्रामा सेंटर की स्थापना 01 करोड़ 41 लाख 35 हजार रूपए की लागत से डीएचएस एवं डीएमएफ मद से की गई है, जहां गंभीर मरीजों का उपचार उन्नत चिकित्सा पद्धति से तात्कालिक रूप से हो सकेगा। इसी तरह डीएमएफ मद से 08 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का भी लोकार्पण उप मुख्यमंत्री साव के द्वारा किया गया। इन चिकित्सा अधोसंरचनाओं के निर्माण से मरीजों को विभिन्न सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा यूनिट में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से बातचीत कर हालचाल जाना। वित्तीय साक्षरता लैब में बच्चे खेल-खेल में बनेंगे जागरूकउप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री साव ने कांकेर प्रवास के दौरान आज पोस्ट ऑफिस के समीप पुराने पुत्रीशाला परिसर में वित्तीय साक्षरता लैब का लोकार्पण किया। उक्त लैब का निर्माण पुराने शाला भवन का जीर्णोद्धार कर किया गया है। डीएमएफ मद से कुल 65 लाख रूपए की लागत से उक्त लैब का निर्माण आधुनिकीकृत ढंग से किया गया है, जहां पर विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को वित्तीय सशक्तिकरण, सायबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता तथा व्यावसायिक निवेश कंपनी अधिनियम की जानकारी, जीएसटी, टीडीएस एवं कर प्रणाली की समझ और शेयर मार्केट से परिचय व शासन की योजना एवं आर्थिक बजट की जानकारी सहित बैंकिंग प्रणाली और निवेश आदि की वित्तीय जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, नगर पालिका कांकेर के अध्यक्ष अरूण कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, उपाध्यक्ष तारा ठाकुर, कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले सहित नागरिक महेश जैन, दिलीप जायसवाल एवं नगर के पार्षद, जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक उपस्थित थे।

खरसिया के चपले में मनरेगा का 'महाघोटाला' : कागजों पर काम पूरा, हकीकत में रात के अंधेरे में चल रही जेसीबी, रोजगार सहायक ने खुद खोली भ्रष्टाचार की पोल!

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत खरसिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत चपले में मनरेगा योजना, जिसे अब वर्तमान में जी-रामजी योजना कहा जाता है, के तहत तालाब गहरीकरण का काम भारी घपले में फंस गया है। सरकारी रिकॉर्ड और गांव में लगे बोर्ड पर तो 8 लाख 75 हजार 500 रुपये का यह काम 31 मार्च 2026 को पूरा हो चुका बताया गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और अभी भी वहां काम चल रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें चल रही हैं और मिट्टी की चोरी-छिपे खुदाई हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नियम के मुताबिक मनरेगा का काम केवल जॉब कार्ड धारक मजदूरों द्वारा ही होना चाहिए, लेकिन यहां मजदूरों की जगह जेसीबी और ट्रैक्टरों का राज चल रहा है। रात में मशीनें मिट्टी निकाल रही हैं और उसे अवैध तरीके से बाहर बेचा जा रहा है। भारी वाहनों के आने-जाने से गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह टूट गई है। धूल का गुबार इतना है कि लोग चलते-फिरते परेशान हो रहे हैं।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड पर साफ-साफ लिखा है कि काम पूरा हो गया, लेकिन मौके पर जाकर देखा जाए तो ताजी खुदाई के निशान हर तरफ दिख रहे हैं। ताजा मिट्टी के ढेर और जेसीबी के पहियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। यह साफ तौर पर शासन को धोखा देने और सरकारी पैसे गबन करने की कोशिश लग रही है।जब इस मामले में रोजगार सहायक से बात की गई तो उन्होंने कई बड़ी बातें मान लीं। उन्होंने कहा कि असल में काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन विभाग की तरफ से 31 मार्च की डेडलाइन के दबाव में कागजों पर काम पूरा दिखा दिया गया। मशीनों से खुदाई की बात पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। शायद कोई बाहर से चोरी-छिपे मिट्टी ले जा रहा होगा। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे।रोजगार सहायक ने यह भी माना कि जहां मशीनों से काम हो रहा है, वहां मस्टर रोल में मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है। इस 8 लाख से ज्यादा के प्रोजेक्ट में दर्जनों मजदूरों को काम मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया कि शुरू में 47-48 मजदूर आ रहे थे, अब धूप ज्यादा पड़ने और शादियों के कारण सिर्फ 5-6 लोग ही एनएमएमएस पर हाजिरी लगा रहे हैं।अब बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जब कागजों पर काम पूरा हो चुका है तो मौके पर खुदाई किसके आदेश से चल रही है? क्या स्थानीय प्रशासन और तकनीकी अधिकारी इस पूरे घपले से अनजान हैं या फिर उनकी चुप्पी में सहमति छिपी हुई है? चपले गांव के इस मामले ने एक बार फिर मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ग्रामीण अब इसकी जांच की मांग कर रहे हैं ताकि मजदूरों का हक बच सके और दोषियों पर कार्रवाई हो।

कांग्रेस ने नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर किया देश की महिलाओं का अपमान -आशीष जैन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सोशल मीडिया के सहप्रभारी आशीष जैन ने कहा कि17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का गिरना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि बहूत ही निंदनीय है जैन ने बतायाइस विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों (दो-तिहाई बहुमत) की आवश्यकता थी, लेकिन पक्ष में केवल 298 वोट मिले, जिससे यह सदन में गिर गया।विपक्षी दलों ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई और इसे तुरंत लागू करने की मांग की, जोकि महिला विरोधी कृत्य को दर्शाता है 27 साल के इंतजार के बाद भी इसे पास न करने में विपक्षी दलों द्वारा बाधा डालना महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक गंभीर षड्यंत्र है।वाकई, यह एक अत्यंत निंदनीय घटना है क्योंकि यह महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के राष्ट्रीय उद्देश्य में बाधा डालती है और राजनीतिक आम सहमति बनाने में विफलता को दर्शाती है।

अग्निवीर लिखित ऑनलाइन परीक्षा के निशुल्क कोचिंग के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

अग्निवीर भर्ती के पंजीकृत युवाओं को मिलेगा 1 माह का निशुल्क कोचिंग

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ जिले के ऐसे युवा जिन्होंने भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किया है वे ऑनलाईन परीक्षा की निशुल्क कोचिंग के लिए 30 अप्रैल तक रोजगार विभाग के पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित है। युवाओं को 4 मई से 4 जून तक 1 माह के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उम्मीदवार के चयन हेतु कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा जून 2026 में संभावित है। इसके बाद शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट हेतु ऑनलाईन परीक्षा के समय टाईपिंग टेस्ट भी देना होगा। भर्ती की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 से प्राप्त कर सकते हैं ।

जनपद पंचायत लैलूंगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडागांव में स्ट्रीट लाइट व अन्य कार्यों में लाखों का खेल, घोटाले के आरोप, जांच की मांग तेज

लैलूंगा /मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत मुडागांव में कराए गए कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने आए आंकड़ों के अनुसार केवल स्ट्रीट लाइट के नाम पर ही कुल 6,55,000 रुपये खर्च दिखाए गए हैं। अलग-अलग प्रस्तावों के माध्यम से 19 जुलाई और 25 जुलाई 2025 सहित विभिन्न तिथियों में बार-बार राशि स्वीकृत कर खर्च दर्शाया गया है, जिसमें 99,000, 88,000, 66,000 और 49,500 जैसी रकम बार-बार दिखाई गई है। इससे एक ही प्रकार के कार्य में बार-बार भुगतान कर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी भारी खर्च दर्शाया गया है, जिसमें नहानी घर निर्माण के लिए 86,000 रुपये निकल गए हैं वर्तमान में ग्राम पंचायत में नहानी रूम मौजूद ही नहीं है , हैंडपंप मरम्मत के लिए 1,57,500 रुपये तथा बोर खनन के दो कार्यों में कुल 2,44,200 रुपये खर्च दिखाया गया है। इस तरह अन्य कार्यों में कुल 4,87,700 रुपये का भुगतान सामने आया है। स्ट्रीट लाइट और अन्य कार्यों को मिलाकर कुल राशि 11,42,700 रुपये तक पहुंच रही है, जो एक छोटी ग्राम पंचायत के हिसाब से काफी बड़ी रकम मानी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर न तो स्ट्रीट लाइट सही ढंग से लगी हैं और न ही अन्य कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं। एक ही तरह के काम को बार-बार दिखाकर राशि निकाले जाने की बात भी सामने आ रही है। मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है और जिम्मेदार अधिकारियों से पारदर्शिता के साथ पूरे खर्च का सत्यापन कराने की मांग उठ रही है

किसान कि जीविक मे आग ! सारंगढ़ वन विभाग की कार्यवाही ने, मशरूम खेती को बनाया राख - किसानों में आक्रोश

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ वन विभाग की कार्यवाही से किसानों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक किसान द्वारा मशरूम खेती के लिए लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर पैरा यानी पराली इकट्ठा किया गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने अवैध कब्जा हटाने के नाम पर देर रात आग के हवाले कर दिया। इस घटना से किसान को भारी नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के पैरा में आग लगा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए यह कार्यवाही की, जो पूरी तरह अनुचित है। किसान का कहना है कि अगर आग हवा के साथ उनके घरों की ओर फैल जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इससे न सिर्फ उनकी संपत्ति बल्कि आसपास के लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है और प्रशासन की इस कार्यवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

घरघोड़ा के अक्षत किशोर मिश्रा नौसेना अकादमी में हासिल किया 30 वां रैंक

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले छोटे से कस्बे घरघोड़ा के एक होनहार युवा ने अपनी मेहनत और अटूट संकल्प से पूरे देश में जिले का नाम रोशन किया है। अक्षत किशोर मिश्रा ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और नौसेना अकादमी (NA) की परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर 30वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) के इंटरव्यू में पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

बचपन से ही मेधावी रहे हैं अक्षत

प्रेम किशोर मिश्रा और माता अर्चना मिश्रा के सुपुत्र अक्षत की शुरुआती शिक्षा घरघोड़ा के सेंट एन्स हाई स्कूल में हुई। वे बचपन से ही अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आते रहे। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें सैनिक स्कूल अंबिकापुर भेजने का फैसला लिया। हालांकि एक मां के लिए अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर भेजना कठिन था, लेकिन देश सेवा के जज्बे के आगे ममता ने भी इस कठिन फैसले को स्वीकार किया। अक्षत ने भी अपने पिता के सपने को अपना लक्ष्य बना लिया और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में पूरे प्रदेश में नौवां स्थान हासिल कर वहां दाखिला लिया।

कड़े अनुशासन और त्याग से मिली सफलता

सैनिक स्कूल में 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान अक्षत ने खुद को एक कुशल छात्र के रूप में निखारा। उन्होंने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह अनुशासित रखा। जहां आज के युवा मौज-मस्ती और सोशल मीडिया में समय बिताते हैं, वहीं अक्षत ने खुद को इन सबसे दूर रखा। सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करना और लगातार मेहनत करना उनकी आदत बन गई। उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें उस वर्दी को हासिल करना है, जिसे पहनकर देश की सेवा की जा सके।

SSB में रचा इतिहास

सेना में अफसर बनने की राह में स्क्रइंटरव्यू सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है। इसमें पांच दिनों तक उम्मीदवार के मनोविज्ञान, शारीरिक क्षमता और नेतृत्व गुणों की बारीकी से जांच की जाती है। अक्षत ने न केवल इस बाधा को पार किया बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंक लाकर यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों के युवाओं में भी आसमान छूने का दम होता है।

युवाओं के लिए रोल मॉडल

अक्षत की इस शानदार उपलब्धि पर उनके बड़े भाई अरुण धर दीवान सहित पूरे परिवार और घरघोड़ा क्षेत्र में खुशी की लहर है।

उनकी सफलता उन हजारों छात्रों के लिए एक मिसाल है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। अक्षत ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो और कर्म के प्रति ईमानदारी, तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है। अब अक्षत उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बनेंगे जहां से देश के महान सैनिक नायक निकले हैं। रायगढ़ का यह लाड़ला अब भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देकर देश की रक्षा करेगा।

रयास विद्यालय के 9वीं के लिए जमा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 21 अप्रैल तक

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु सभी वर्ग के विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन 17 अप्रैल तक आमंत्रित किया गया था। विद्यार्थी द्वारा आवेदन करने में यदि कोई त्रुटि हुई है तो 21 अप्रैल तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सारंगढ़ कोसीर रोड कालेज के पास कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार किया जा सकता है। 21 अप्रैल के बाद त्रुटि सुधार के लिए मौका नहीं मिलेगा और आवेदन निरस्त पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। प्रयास आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट तथा एनडीए जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। यह प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को निर्धारित है। इच्छुक विद्यार्थी विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भाजपा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी –राजेश

कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में थी और है

जांजगीर चांपा/मूक पत्रिका

131 वां संविधान संशोधन अधिनियम के संसद में गिरने पर इस महत्वपूर्ण विषय पर जिला कांग्रेस कमेटी का जांजगीर चांपा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) 106 वां संविधान संशोधन 2023 में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है जो कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर पश्चात कानून भी बन चुकी है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 131 वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। सीटों के परिसीमन पर भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया है, अतः वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक रही है, जिसके फलस्वरूप पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका। अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से ही आज देशभर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

सरकार ने 131 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया

* भाजपा सरकार का परिसीमन बिल पर देश के अन्य राज्यों को आपत्ति थी, भाजपा आरक्षण सामने रख कर परिसीमन बिल पास करना चाहती है।

भाजपा 2011 के जनगणना को आधार मान कर परिसीमन करना चाहती है।

* जब 2026-27 की जनगणना शुरू है तथा सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है तो जनगणना के बाद आये नये आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा ?* महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतजार किये बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती सरकार ? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार है।* सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी उसने ऐसा क्यों नहीं किया?* जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कानून बन चुका है 2036 से मूर्त रूप लेगा संशोधन से तुरंत लागू हो जाता।* भाजपा की मंशा महिला आरक्षण देना नहीं बल्कि मन मुताबिक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, अपने लिए स्थाई सत्ता सुनिश्चित करना है।

भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है1. संसद में जो विधेयक गिरा उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था राज्यों में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें ।

2. परिसीमन विधेयक - जिसमें परिसीमन के लिये 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की जा रही थी।3. विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गयी थी ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके।

यह विधेयक इसलिए गिरा–भाजपा सरकार का परिसीमन बिल पर देश के अन्य राज्यों को आपत्ति थी भाजपा आरक्षण सामने रख कर परिसीमन बिल पास करना चाहती है।

* भाजपा 2011 के जनगणना को आधार मान कर परिसीमन करना चाहती है। जब 2026-27 की जनगणना शुरू है तथा सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है। जनगणना के बाद आये नये आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा? महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतजार किये बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती सरकार ? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार है।* सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कानून बन चुका है 2036 से मूर्त रूप लेगा संशोधन से तुरंत लागू हो जाता।

उपकोषालय अधिकारी पर रिश्वतखोरी का लगा गंभीर आरोप , डिलवरी क्लेम के लिए 5 हजार ऑनलाइन पेमेंट

लैलूंगा/मूक पत्रिका

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा उपकोषालय में रिश्वतखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि उपकोषालय में पदस्थ अधिकारी मुकेश नायक ने एक महिला कर्मचारी से मेडिकल बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की और अंततः 5000 रुपये वसूल लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजेश कुमार पटनायक ने बताया कि उनकी पत्नी सिम्मी पटनायक (सहायक ग्रेड-03) ने सिजेरियन डिलीवरी के बाद 44,425 रुपये का मेडिकल क्लेम प्रस्तुत किया था। आरोप है कि बिल पास करने के लिए संबंधित अधिकारी ने 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की। शिकायत के मुताबिक, पहले 10,000 रुपये की मांग की गई, जिसे बाद में 8000 रुपये तक कम किया गया और अंततः दबाव बनाकर 5000 रुपये ले लिए गए। खास बात यह है कि यह लेन-देन डिजिटल माध्यम से किया गया। आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए नंबर भेजकर फोनपे के माध्यम से राशि ट्रांसफर कराई गई, जिसके बैंक स्टेटमेंट, चैट और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे सबूत भी मौजूद बताए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि क्षेत्र के विभिन्न विभागों में बिल पास कराने के लिए कमीशन लेने की यह प्रथा आम हो चुकी है। कई मामलों में फाइलों को जानबूझकर लंबित रखा जाता है, जिससे संबंधित कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा सके।पीड़ित पक्ष ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और कलेक्टर रायगढ़ से की है तथा निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा।

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं।

अक्षय तृतीया पर भक्ति,परंपरा और उत्साहः परशुराम जन्मोत्सव में सजी आस्था की झांकी शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

रामानुजगंज /मूक पत्रिका

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर नगर में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा,उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। सुबह शिव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई,जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और समाज की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की गई। पूजा के बाद नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी के साथ श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति गीतों और जयघोषों के बीच आगे बढ़े। शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां नागरिकों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान रखा गया, वहीं श्रद्धालुओं के लिए पानी और प्रसाद की भी व्यापक व्यवस्था की गई। शोभायात्रा पुनःशिव मंदिर प्रांगण पहुंची,जहां सामाजिक संवाद का दौर चला। वक्ताओं ने समाज में आपसी सौहार्द और मजबूत संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों मे योगेंद्र ओझा, विजय नाथ चौबे, लाल बिहारी चौबे,उमाशंकर चौबे और सतनारायण तिवारी का माल्यार्पण, शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भंडारे के साथ हुआ। आयोजन में मधुसूदन चौबे, पारस पांडे, डॉ.गोरखनाथ पांडे,विपिन पाठक, दिनेश चौबे, ऋषि द्विवेदी, श्याम कुशल पांडे, अरविंद दुबे, मनोज दुबे, अनुपम पांडे, विकास दुबे, अनिल पांडे, राजा तिवारी, जय चौबे, दिवाकर द्विवेदी, विनय पांडे, रमेश मिश्रा, विष्णु पांडे, उज्ज्वल तिवारी,वेद प्रकाश तिवारी, निशांत चौबे, दामोदर मिश्र, रितेश पांडे,आनंद मिश्रा, सूरज मिश्रा, संतोष पांडे, आशु चौबे, दीपक दुबे, आनंद चौबे, बिट्टू चौबे, अर्पित तिवारी, सूर्यमणि पांडे सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।

आँगन बाड़ी कार्यकर्ता संघ ने बिलासपुर के जिला परियोजना–कार्यक्रम अधिकारी से बेलगहना सेक्टर के सुपरवाईजर के भ्रष्टाचार की शिकायत की

संघ की जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने की शिकायत

कोटा/मूक पत्रिका

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले संघ की जिला अध्यक्ष मंजू कोमल मेश्राम और संघ के पदाधिकारियों ने बेलगहना सेक्टर के पर्यवेक्षक किर्ति किरण मोगरे के भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत बिलासपुर जिला परियोजना एवम कार्यक्रम अधिकारी से की, और उचित एवम निष्पक्ष कार्यवाई की मांग की है। अपने शिकायत आबेदान में उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि बेलगहना सेक्टर सुपरवाइजर किर्ति किरण मोगरे के द्वारा बेलगहना सेक्टर में पैसों की मांग लगभग सभी

कार्यों के लिए की जाती है तथा नहीं देने पर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाना एवं उनके परिजनों से गाली गलौज एवं बदतमीजी किये जाने की गंभीर शिकायत काफी समय से प्राप्त होती रही है इसके विस्तृत विवरण के लिए शिकायत की प्रति साथ में संलग्न है। महोदय इनके द्वारा बेलगहना सेक्टर में सहपर्यवेक्षक के रूप में एक कार्यकर्ता जिनका नाम ललिता यादव है को रखा गया है उनको इन्होंने अपनी आईडी दी हुई है उसके द्वारा इनका समस्त लेनदेन किया जाता है तथा उसी के द्वारा अपना समस्त कार्य (शासकीय कार्य भी) कराया जाता है और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। महोदय इस प्रकार से अपना असिस्टेंट रखना शासकीय सेवा नियमावली के एकदम विरुद्ध है गैर कानूनी है और इन सभी के साक्ष्य उपलब्ध हैं और संलग्न हैं। कीर्ति किरण मोगरे के द्वारा पूर्व में भी भ्रष्टाचार किया गया था जब वह चपोरा सेक्टर में पदस्थ थी उस समय मृत व्यक्तियों का नाम शामिल कर दिया था इस कारण उन्हें पहले भी हटाया जा चुका है लेकिन उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है उल्टे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।महोदय वर्तमान में जो शिकायत प्राप्त हुई है वह बहुत ही गंभीर है और अपमानजनक है अतः इस संबंध में निवेदन है कि उन पर कठोर कार्यवाही की जाए और शीघ्र ही उन्हें वहां से हटाकर, तब जांच की जाए, जिससे जांच निष्पक्ष हो सके अन्यथा उनके द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं को भी भयभीत कर प्रभावित किया जाएगा। अतः उपरोक्त सभी संबंधों में महोदय से अपेक्षा है कि शीघ्र ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और ऐसा नहीं होने पर हमारा छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला अध्यक्ष के द्वारा उक्त शिकायत पत्र के माध्यम से अधिकारियों को अपने विरोध,निवेदन से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में लीपापोती न कि जाए निष्पक्ष जाँच की जाए और जांच के पहले वंहा से सुपरवाइजर को बाहर भेजा जाय क्योकि उनके द्वारा लगातार कार्यकर्तो पर दबाव व भय का वातावरण निर्मित की जा रहा है जो उचित नही है। यदि उचित निष्पक्ष जांच न करके सुपरवाइजर को बचाने की कोशिश की जाती है तो संघ आंदोलन का मार्ग अपनाएगा जिसकी सारी जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की होगी।

कांग्रेस ने नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर किया देश की महिलाओं का अपमान -आशीष जैन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सोशल मीडिया के सहप्रभारी आशीष जैन ने कहा कि17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) का गिरना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि बहूत ही निंदनीय हैजैन ने बताया इस विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों (दो-तिहाई बहुमत) की आवश्यकता थी, लेकिन पक्ष में केवल 298 वोट मिले, जिससे यह सदन में गिर गया।

विपक्षी दलों ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई और इसे तुरंत लागू करने की मांग की, जोकि महिला विरोधी कृत्य को दर्शाता है

27 साल के इंतजार के बाद भी इसे पास न करने में विपक्षी दलों द्वारा बाधा डालना महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक गंभीर षड्यंत्र है।

वाकई, यह एक अत्यंत निंदनीय घटना है क्योंकि यह महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के राष्ट्रीय उद्देश्य में बाधा डालती है और राजनीतिक आम सहमति बनाने में विफलता को दर्शाती है।

विधायक सुश्री लता उसेण्डी की अध्यक्षता में जीवन दीप समिति की बैठक संपन्न

कोंडागांव/मूक पत्रिका

बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी की अध्यक्षता में शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी में जीवन दीप समिति की सामान्य सभा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जुगबती पोयाम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रदमा बघेल, श्रीमती भगवती नेताम उपस्थित रहे। बैठक में विधायक ने क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष जोर देते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सोलर सिस्टम में सुधार करने तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उनके मानदेय में वृद्धि के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में गत वर्ष की आय-व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई तथा इस वर्ष के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी सहित समिति के सदस्यगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राम अंडोला में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर सम्पन्न, शिविर में 164 आवेदन प्राप्त, मौके पर 87 निराकृत 77 प्रगति पर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप ÷प्रशासन गांव की ओर÷ थीम पर सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम अंडोला विगत दिवस जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे और जिला पंचायत सदस्य लता लक्षमे, संतोषी खटकर और अन्य जनप्रतिनिधि के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। शिविर में मांग के 162 और शिकायत के 2 आवेदन की प्राप्ति हुई जिसमें मौके पर 87 आवेदन निराकृत किया गया और 77 आवेदन प्रगति पर है। शिविर में जिला स्तर के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने ग्रामीणों को भारत नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्ति और जल संरक्षण जागरूकता के लिए शपथ दिलाई। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा किसान पुस्तिका, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पीएम आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक दवा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा माताओं को सुपोषण किट, महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार मछली पालन विभाग द्वारा हितग्राहियों को जाल एवं आइस बॉक्स, खाद्य विभाग द्वारा पीएम उज्जवला गैस, राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मरीजों को पोषण आहार शिविर में ओपीडी के माध्यम से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग को ट्रायसायकल और वृद्धजनों को छड़ी प्रदान किया गया।

स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों में कमी, महिलाओं को मिला समय और आत्मनिर्भरता का अवसर

ग्राम सरवानी में जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन : घर-घर नल से बदली दिनचर्या, स्वास्थ्य और जीवन स्तर

गांव में स्वच्छता व सामाजिक भागीदारी को मिला बढ़ावा

महिला सशक्तिकरण से सामुदायिक विकास तकः आत्मनिर्भरता और स्वच्छता की ओर बढ़ता ग्राम सरवानी

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सरवानी आज जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। 297 घरों और 1203 की आबादी वाले इस ग्राम में 1 प्राथमिक शाला, 1 माध्यमिक शाला तथा 3 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक ग्राम सरवानी जल संकट से जूझ रहा था, जहां ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को पेयजल के लिए कुएं और दूरस्थ हैंडपंपों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की निवासी श्रीमती सुनीता सिदार का जीवन भी इसी संघर्ष का प्रतीक था, जहां उन्हें प्रतिदिन घंटों कतार में खड़े रहकर पानी लाना पड़ता था और कई बार पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती थी, जब तालाब और खुले स्रोतों का दूषित पानी उपयोग करने की मजबूरी के कारण परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते थे तथा बच्चों में पेट दर्द, बुखार और त्वचा संबंधी समस्याएं आम थीं। इन परिस्थितियों के बीच जल जीवन मिशन के तहत ग्राम में पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसने परिवर्तन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। कुछ ही समय में सुनीता सिदार के घर में भी नल कनेक्शन स्थापित हो गया, जिससे उनके जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। अब उनके घर में नियमित रूप से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, जिससे पानी के लिए भटकने और घंटों इंतजार करने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। इससे उनकी दिनचर्या सरल और व्यवस्थित हुई है तथा वे अपने परिवार को अधिक समय दे पा रही हैं और बच्चों को समय पर स्कूल भेजना संभव हो गया है।

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से परिवार के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बीमारियों में कमी आई है और बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं समय और श्रम की बचत ने सुनीता सिदार को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सिलाई एवं छोटे घरेलू व्यवसाय की शुरुआत की है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह परिवर्तन केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे ग्राम सरवानी में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। गांव में स्वच्छता का स्तर बेहतर हुआ है और लोग स्वच्छ पेयजल के महत्व को समझने लगे हैं।

महिलाएं अब सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा है। जल जीवन मिशन ने ग्राम सरवानी को केवल पेयजल सुविधा ही नहीं दी, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार भी प्रदान किया है। श्रीमती सुनीता सिदार की यह कहानी इस बात का सशक्त प्रमाण है कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आज ग्राम सरवानी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर घर में बहता स्वच्छ जल उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहा है।

संपादकीय

महंगाई -बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की जेब पर दोहरी मार

यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। यह विचित्र बात है कि एक ओर सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, तो दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर जरूरी खर्च में कटौती और आर्थिक परेशानियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जब आय के साधन सीमित हों, तो आम आदमी की यही अपेक्षा होती है कि जरूरी वस्तुओं के दाम उसकी पहुंच में हों, ताकि परिवार के भरण-पोषण का संकट पैदा न हो।मगर हाल के वर्षों में आमदनी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4 फीसद हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.2 फीसद के स्तर पर थी। खबरों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण खुदरा महंगाई में वृद्धि हुई है। मगर सवाल है कि अगर सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या स्थिर करने के लिए उचित कदम उठा रही है, तो फिर महंगाई में उछाल कैसे आ रहा है?यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। आमदनी में स्थिरता और घटती क्रयशक्ति की स्थिति में जब आवश्यक वस्तुओं पर आम लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उनके लिए परेशानियां पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल, मार्च में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा रहा।खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि उपभोक्ताओं की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई को ही आधार बनाता है। सरकार का दावा है कि खुदरा महंगाई अभी रिजर्व बैंक के चार फीसद के औसत अनुमान से नीचे बनी हुई है। मगर, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर महंगाई दर चार फीसद के दायरे से ऊपर जाती है, तो फिर कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है।आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में फरवरी की तुलना में महंगाई दर का बढ़ना पश्चिम एशियाई संकट के शुरुआती प्रभाव का संकेत है। यानी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मोर्चा फिर से खुलता है और यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो आवश्यक वस्तुओं के दाम किस तेजी से बढ़ेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में आलू-प्याज और कुछ दालों की कीमतों की महंगाई दर घटी है, लेकिन सोने-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई।बिजली, गैस और अन्य ईंधन श्रेणी में खुदरा महंगाई मार्च में 1.65 फीसद रही, जबकि फरवरी में यह 1.52 फीसद के स्तर पर थी। यानी आम लोगों के लिए राहत कम और मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। यही नहीं, शहरी इलाकों में 3.11 फीसद की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.63 फीसदी रही, जहां रोजगार और आय के साधन सीमित होते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय नहीं किए, तो आने वाले दिनों में यह संकट और ज्यादा गहराएगा।

नारी शक्ति वंदनः विकसित भारत 2047 की आधारशिला

डॉ. पंकज शुक्ला
चेयरमैन ग्राम्या
प्रेसिडेंट- आर एस आर ई

भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ नारी की गरिमा और शक्ति उसके सांस्कृतिक एवं सामाजिक ताने-बाने की आधारशिला है। यह शाश्वत विचार–÷यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता÷ अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ दिव्यता का वास होता है–आज भी भारत की विकास यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, नारी सशक्तिकरण एक कल्याणकारी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास की केंद्रीय धुरी बन चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस परिवर्तन का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत की समावेशी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और नारी-नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को दर्शाता है।

पिछले एक दशक में भारत ने शासन व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन देखा है, जहाँ महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नेता, उद्यमी और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार बनकर उभरी हैं। यह परिवर्तन एक सशक्त और समन्वित नीतिगत ढांचे के माध्यम से संभव हुआ है, जिसमें जन-धन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरिमा और स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सुरक्षा और सम्मान, मुद्रा योजना के माध्यम से उद्यमिता, तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया गया है। ये सभी पहलें मिलकर नारी-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की मजबूत नींव तैयार करती हैं।

आज महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था में एक सशक्त योगदानकर्ता के रूप में उभर रही हैं। 8 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, लगभग 20 प्रतिशत स्वस्थ उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित हैं, और कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान में महिलाओं का लष्ठक में योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, जो उचित अवसर, संसाधन और बाजार उपलब्ध होने पर 30 प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि न केवल आर्थिक उन्नति को गति देगी, बल्कि भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी।

हालांकि, नीतिगत दृष्टि का वास्तविक प्रभाव तभी संभव है जब उसका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो। पिछले एक दशक में लह्डुद्व4ड्ड के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्थानीय स्तर पर ठोस परिणामों में परिवर्तित किया जाए। 5 लाख से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए, स्वयं सहायता समूहों को उद्यमों में परिवर्तित किया गया, किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त किया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया।

हमारी पहलें–Mission Shakti, Mission Annapurna, Cooperative to Corporate, Village Development Committees (VDC), Poshan Abhiyan आधारित कार्यक्रम, ÷श्रृंगार बने हथियार÷ और ÷सोच से समृद्धि÷–प्रधानमंत्री जी के ÷सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास÷ के सिद्धांत के अनुरूप समग्र परिवर्तन के मॉडल के रूप में कार्य करती हैं। ये पहलें महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं, जहाँ वे आर्थिक गतिविधियों की संचालक, स्थानीय संसाधनों को आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करने वाली उद्यमी, और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बनती हैं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने, बाजार तक सीधी पहुंच प्राप्त करने, डिजिटल और वित्तीय प्रणालियों से जुड़ने तथा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकज विकसित करने में सक्षम बनाया गया है। इससे उनकी आजीविका न केवल स्थायी बनी है, बल्कि विस्तार योग्य भी हुई है। इसका प्रभाव बहुआयामी है–आर्थिक स्तर पर यह रोजगार सृजन, आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है, जबकि सामाजिक स्तर पर यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही, यह स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर समाज में समानता और सहभागिता की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस परिवर्तन को और अधिक सशक्त बनाता है, क्योंकि यह महिलाओं को शासन और नीति निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह केवल राजनीतिक भागीदारी का विस्तार नहीं, बल्कि महिलाओं को भारत के विकास की दिशा तय करने वाले नीति-निर्माता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज जब विश्व लैंगिक समानता की दिशा में प्रयासरत है, भारत एक ऐसा समग्र मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का संतुलित समन्वय करता है। यह मॉडल केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसर, क्षमता और नेतृत्व को केंद्र में रखता है।

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जाएगी। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण, समावेशी विकास सुनिश्चित करना और वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना–ये सभी लक्ष्य तभी संभव हैं जब महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास निरंतर और प्रभावी रूप से जारी रहें।

आगे की राह स्पष्ट है–शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और नेतृत्व विकास पर निरंतर निवेश करना होगा। जब महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त होती हैं, तो वे राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन जाती हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक सुधार नहीं, बल्कि भारत की सोच, शासन और विकास यात्रा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाएं केवल विकास की सहभागी नहीं, बल्कि उसकी सबसे सशक्त संचालक हैं।

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, उसकी गति और दिशा उसकी महिलाओं की शक्ति, संकल्प और नेतृत्व से निर्धारित होगी। और इसी शक्ति के माध्यम से भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक नेतृत्व स्थापित करेगा जो समावेशी, संतुलित और मानवीय विकास की दिशा में मार्गदर्शन करेगा ।

समाज और राष्ट्र में सत्यं शिवं सुंदरम् की स्थापना ही संघ का उद्देश्य

कृष्णमोहन झा/

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग स्थित श्री केशव स्मृति मंदिर में संघ के घोष पथक (बैंड मंडली) इतिहास पर आधारित हस्तलिखित ग्रंथ %राष्ट्र स्वराधना% के विमोचन समारोह के मंच से अपने उदबोधन में कहा कि संघ को अपने 100 साल के सफर में न तो किसी की कृपा की आकांक्षा रही न ही किसी की अव कृपा उसके सफर में कभी अवरोध पैदा कर सकी। स्वयंसेवकों के परिश्रम से संघ आज देश का दिशा दर्शन करने वाली ताकत बन चुका है। इसके बावजूद इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराने की संघ की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह अपने सभी कार्यों का श्रेय पूरे समाज को देना चाहता है। मोहन भागवत ने %राष्ट्र स्वराधना% ग्रंथ को संघ के स्वयंसेवकों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ कर वे यह जान सकेंगे कि संघ ने पिछले 100 सालों में क्या किया है और आगे क्या करना चाहिए। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संघ की विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रनिर्माण में समर्पित भाव से अपनी पूरी शक्ति लगाई है। इससे यह स्पष्ट है कि संघ केवल एक संगठन नहीं है बल्कि विचारधारा है जिसका मूल उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र की सेवा करना है।मोहन भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष को उत्सव के आयोजन नहीं बल्कि आत्मावलोकन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें पूर्वजों का स्मरण करते हुए और अधिक उन्नत स्थिति की ओर आगे बढने का प्रयास करना है। पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आगे बढाना स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी है।संघ प्रमुख ने समाज को संगठित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और अधिक संगठित और व्यापक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसमें समाज की भी सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया।

संघ प्रमुख ने घोष दल के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष दल में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं जिनके स्वर एवं ध्वनि अलग अलग होते हुए भी स्वयं सेवक एक ही ताल पर चलते हैं। इससे समन्वय एवं एकता की भावना मजबूत होती है। जब कोई कार्य मन से एवं पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो उसका परिणाम भी उसी रूप में प्रकट होता है और सत्य ं शिवं सुंदरम् की अनुभूति होती है।मोहन भागवत ने अपनी इस बात को रेखांकित किया कि समाज और राष्ट्र में सत्यं शिवं सुंदरम् की स्थापना ही संघ का उद्देश्य है। सरसंघचालक ने कहा कि संघ के सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य संस्कारों का निर्माण करना है। सुदृढ़ शरीर और संस्कारित मन के समन्वय से गुणवत्ता पूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ना ही लक्ष्य है। इस दृष्टि से %राष्ट्र स्वराधना% का हस्तलिखित इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय बीत जाता है, कार्य खड़ा हो जाता है परन्तु मौलिक गुणवत्ता शुरुआत में थी उसे अंत तक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमने विकट परिस्थिति में कार्य कैसे खड़ा किया और किस उद्देश्य से किया उसका सदैव स्मरण कराने का कार्य यह ग्रंथ करेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवक पेशेवर गायक या वादक नहीं होते लेकिन अपने दैनिक कार्यों को संभालते हुए, बिना कागज सामने रखे इतनी सुंदर रचनाएं कैसे प्रस्तुत कर लेते हैं इस पर लोगों को आश्चर्य होता है परन्तु चमत्कार करना संघ का उद्देश्य नहीं होता ।वह तो अपने आप घटित हो जाता है। पूर्व स्वयं सेवकों के सदुण इन रचनाओं में मिलते हैं और दिखाई देते हैं। भाव तभी उत्पन्न होता है जब वादक पूरे मन से वादन करता है। इसे केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात समझ कर करना चाहिए।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

फांसी जैसी सजा से ही रुकेंगी पुलिस हिरासत में मौतें

(योगेंद्र योगी)

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं।

देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात क़रीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

इसी तरह लुधियाना जिले में करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई थी। मौत के मामले में लुधियाना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दीं। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी।

पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया है। जुलाई 2024 को मध्यप्रदेश के बिलाखेड़ी निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने 8 लाख रुपये की कथित चोरी के आरोप में उसे हिरासत में लिया था। हिरासत में मौत के बाद उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। इस जांच के सिलसिले में एजेंसी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिरासत में हुई मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी फरार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है।कोर्ट ने कहा कि इससे साफ़ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराज़गी जताई थी। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की। जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा, केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं।

क्या नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक, प्रशासनिक व राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है?

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है। यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं।

(कमलेश पांडे)

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है।

हमारे देश के राजनेता भले ही चुनावों के दौरान दलित-महादलित-आदिवासी, ओबीसी-ईबीसी, अल्पसंख्यक-पसमांदा और गरीब सवर्ण आदि से जुड़े सामाजिक न्याय सम्बन्धी तरह-तरह की बातें करते हैं, ममनगढ़ंत आंकड़े गिनाते/बताते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे श्रमजीवियों का अंतहीन शोषण होता रहता है, जिससे उनका मुंह फेरे रहना या फिर किसी बड़े आंदोलन के बाद सक्रिय होना उनके नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाता है।

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है।

यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं। विपक्ष का काम संसद में, विधान मंडल में इन्हीं पहलुओं पर तर्कसंगत बहस करना है, लेकिन वह भी नीतिगत नकारापन का शानदार नमूना बन चुका है। दिलचस्प तो यह कि पहले सत्ताधारी यूपीए के वक्त एनडीए विपक्ष में था और अब सत्ताधारी एनडीए के वक्त यूपीए/इंडिया गठबंधन विपक्ष में है।

चूंकि दोनों पूंजीवादी गठबंधन हैं और अपने आर्थिक मोहपाश में जनोन्मुखी समाजवादी व वामपंथी सियासत को बांध चुके हैं, जिससे सबकुछ गड्डमड्ड हो चुका है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद और कहीं सम्प्रदायवाद के नाम पर परस्पर बंटी हुई जनता को अपनी मौलिक जरूरतों का एहसास ही नहीं है।

काबिलेगौर है कि शहरों/महानगरों या गांवों में जो आमतौर पर वेतन स्ट्रक्चर होता है, उससे कोई युवा या वयस्क अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सकता है क्या? जवाब होगा- संभव नहीं ! कोढ़ में खाज यह कि तरह तरह के मित्रों- शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र आदि के मार्फ़त सरकारी क्षेत्र भी इन्हीं पूंजीवादी मानसिकता को तरजीह देता आया है, जिस पर उदार हृदय से बहस करने और भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है।

सवाल है कि जिन शहरों में फ्लैट्स या जमीन की कृत्रिम कीमतें आसमान छूती हों, वहां के दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी, अंशकालिक/पूर्णकालिक श्रमिकों के वेतनमान, और भारतीय कानूनों से अधिकारियों/उद्योगपतियों के खिलवाड़ से पूरी श्रम व्यवस्था विस्फोटक कगार पर खड़ी है। शहरों में बढ़ता झुग्गी-झोपड़ी कल्चर किसी नैतिक महामारी जैसा प्रतीत होता है।

सुलगता सवाल है कि निजी क्षेत्र में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं निजी कम्पनियों में मिलती है। प्रोपर्टी इंडस्ट्री की तरह आधा ब्लैक सैलरी और आधा व्हाइट सैलरी वाली आंखों में धूल झोंकने वाली व्यवस्था से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सरकारी क्षेत्रों की तरह आवासीय सुविधाओं से निजी क्षेत्र के श्रमिकों को वंचित क्यों रखा जाता है? नौकरी बाजार में श्रम ठेकेदार पैदा करने से किसके हित सधते हैं? सवाल अनेक हैं, लेकिन उत्तर एक- राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक सांठगांठ से जारी नीतिगत भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है, जो किसी बड़ी जनक्रांति के बाद ही करवट लेगी।

जरा कल्पना कीजिए कि जब नरेंद्रमोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी मजदूर विरोधी परिस्थिति है तो पूर्व की सरकारों में कैसा जंगलराज रहा होगा, विचारणीय पहलू है। मजदूर शोषण कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम भारतीयों के भविष्य के साथ एफडीआई आकर्षित करने के चक्कर में घोर अन्याय हो रहा है, जिससे बचे जाने की जरूरत है।

अब नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं। चूंकि नोएडा में मजदूरों का हिंसक आंदोलन वेतन वृद्धि की मांग पर केंद्रित है, जो हरियाणा की 35 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी से प्रेरित है। लिहाजा, योगी सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए। बताया गया कि यह प्रदर्शन फेज-2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूरे नोएडा में फैल गया, जहां पेशेवर विपक्षी आंदोलनों के तर्ज ओर तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने संवाद के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है और अविलंब इसके निर्णयों को लागू करने की जरूरत है।

जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की बात है तो योगी सरकार ने आंदोलन को साजिश, नक्सलवाद या राजनीतिक हाथ बताया, जिससे सहमत होना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के हिंसक होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत भी नहीं हैं। वहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की पूंजीपति पक्षधर नीति को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर शोषण का आरोप लगाया, जो अतिरेक है। चूंकि कांग्रेस और सपा ने सरकार की आलोचना की, इसलिए केंद्र भी सतर्क है।

इस अप्रत्याशित आंदोलन का प्रमुख निहितार्थ यह है कि यह आंदोलन श्रम नीतियों पर बहस तेज कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों से अंतरराज्यीय दबाव बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को मजदूर वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को कानून-व्यवस्था पर खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ी।दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी। यह कोरा सच है कि नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक-प्रशासनिक-राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है। नोएडा मजदूर आंदोलन 2027 यूपी विधानसभा चुनावों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह श्रमिक असंतोष को विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी ताजा घटना होने से विश्लेषण अनुमानित हैं, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इससे विपक्ष को लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की पूंजीपति नीति बताकर मजदूरों का समर्थन किया, जो पीडीएयानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और विपक्षी एकता का संकेत दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक वोट (गौतमबुद्धनगर सीटें) प्रभावित हो सकते हैं। इससे भाजपा की जमीनी चुनौती बढ़ेगी और हिंदुत्व दम तोड़ देगा, इसलिए योगी सरकार ने वेतन, ओवरटाइम सम्बन्धी निर्देश देकर क्षतिपूर्ति की कोशिश की, लेकिन इसे साजिश बताकर विपक्ष को और हवा मिली। कानून-व्यवस्था का सवाल उठा, जो भाजपा के मजबूत सरकार वाले नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे दिल्ली-एनसीआर में आंदोलन के फैलाव से पश्चिम यूपी की सीटें जोखिम में पड़ सकती हैं। वहीं, श्रम मुद्दा, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी से जुड़कर 2027 में प्रमुख हो सकता है, खासकर ग्रेटर नोएडा-जेवर जैसे क्षेत्रों में। इसलिए यदि समाधान न हुआ तो विपक्ष मजबूत, वरना भाजपा इसे विकास के पक्ष में पलट सकती है। कुल मिलाकर, नोएडा रणभूमि बन चुका है।वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

अग्रोहा प्लांट की गिद्ध नजर है चिराईपानी की आरक्षित भूमि पर, हथियाने की चल रही साजिश

सरपंच और सचिव को लिखित में शिकायत कर ग्रामीणों कहा - प्लांट ने किया अतिक्रमण तो होगा आंदोलन

रायगढ़ /मूक पत्रिका

जिले में उद्योग जगत ने तो हद ही कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता की लाठी इन्हीं को सौंप दी गयी है। जिसे जहाँ मौका मिल रहा, वहीं कब्जा कर रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि शासकीय जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अग्रोहा प्लांट द्वारा गाँव की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यही नहीं, ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिराईपानी के जागरूक युवकों ने एकजुट होकर सरपंच एवं पंचायत सचिव को लिखित शिकायत सौंपते हुए पाली स्थित 'अग्रोहा प्लांट' के खिलाफ तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग भी की है। न्याय नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान भी किया है।ग्रामीणों की मानें तो चिराईपानी के सरकारी जमीन, जो 'छोटे झाड़ के जंगल' के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है,

इस पर प्लांट द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह भूमि गांव के सार्वजनिक उपयोग और विकास कार्यों के लिए आरक्षित है। शिकायत में आरोप है कि संबंधित जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई की गई है और भूमि को समतल करने के लिए बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, बाउंड्री वॉल निर्माण के उद्देश्य से लोहे के खंभे भी गाड़े जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों ने अग्रोहा कंपनी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य गोपाल अग्रवाल और जनपद सदस्य श्रीमती फूलमति धनवार से भी हस्तक्षेप कर कब्जा हटवाने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्य न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि गांव के सामूहिक अधिकारों का भी हनन है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं में नटराज डनसेना, महेंद्र कुमार, अर्जुन यादव, नीरज डनसेना सहित बड़ी संख्या में शामिल अन्य ग्राम वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलन जैसे बड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। अब सवाल उठता है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई पीढ़ियों से निवासरत जनता के घर पर जब बुलडोजर चल सकता है तो उद्योगपतियों के इस तरह के अवैध कब्जे पर खामोशी क्यों? क्षेत्र में स्थापित ऐसे कई उद्योग हैं जिनके ऊपर शासकीय और वन भूमि पर अवैध कब्जा के आरोप हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई।

एसबीआई मेन ब्रांच और चेंबर ऑफ कॉमर्स सारंगढ़ ने बांटे 10 एवं 20 के नए नोट

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला मुख्यालय सारंगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा और चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के सहयोग से फुटकर विक्रेता, बड़े विक्रेता, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य एवं जो सदस्य नहीं है उनको भी छोटे नए नोटों का वितरण किया। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक लालबाबू प्रसाद गुप्ता एवं मुख्य रोकडिया निमेश नायक ने सभी व्यापारियों एवं ग्राहकों से आग्रह किया है कि इन नोटों को बाजार में प्रचलन में लाकर चिल्लर नोटों की समस्या को दूर करें। मुख्य प्रबंधक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने सरिया, बरमकेला, बिलाईगढ़, भटगांव और सरसीवा हेतु गाताडीह चंद्रहासिनी शाखा के माध्यम से भी छोटे नोटों का वितरण, हाट बाजार, चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के सदस्य एवं अन्य नागरिक, लोगो के बीच सभी स्तर पर किया है। इस काम को संपन्न करवाने में चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के पदाधिकारी महेंद्र अग्रवाल, संगीत सिंह ठाकुर, घनश्याम बंसल, देवेंद्र बानी, नाथूलाल केडिया एवं अन्य पदाधिकारी लोगों का भरपूर सहयोग मिला।

अक्षत किशोर मिश्रा ने नौसेना अकादमी में हासिल किया अखिल भारतीय 30 वा रैंक और एसएसबी में सर्वाधिक नंबर

रायगढ़/मूक पत्रिका

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षा में सम्मिलित होकर घर घोड़ा निवासी अरुण धर दीवान के छोटे भाई प्रेम किशोर मिश्रा और माता अर्चना मिश्रा के बेटे अक्षत किशोर मिश्रा ने देश की सेवा सबसे गौरवशाली अध्याय की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। अक्षत की इस उपलब्धि से रायगढ़ का मान देश में बढ़ा है।बचपन से होनहार अक्षत की प्रारम्भिक शिक्षा घरघोड़ा के सेंट एन्स हाई स्कूल में पूरी हुई। नर्सरी से कक्षा पाचवी तक की पढाई पूरी करने वाले अक्षत ने अनवरत सभी कक्षाओं प्रथम स्थान हासिल किया। अक्षत की प्रतिभा को देखते हुए पिता प्रेम मिश्रा ने अंबिकापुर सैनिक स्कूल में दाखिले का निर्णय लिया। इस निर्णय में मां की ममता आड़े आ रही थी लेकिन देश सेवा का जज्बा अंततः माता की ममता पर भारी पड़ी। पिता प्रेम के बेटे अक्षत के मन में देश सेवा का बीजारोपण किया वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगा और बेटा अक्षत भी अम्बिकापुर स्थित सैन्य स्कूल में दाखिले के लिए मानसिक रूप से तैयार हुआ। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश परीक्षा के कठोर नियमों की बाधाओं को अक्षत ने हंसते हुए पार किया और प्रवेश परीक्षाम पूरे छत्तीसगढ़ में नौवां स्थान हासिल किया। कक्षा छठवीं से 12 वीं तक की पढाई सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में करते हुए होनहार अक्षत में छात्रों का कुशल प्रतिनिधित्व भी किया। देश रक्षा का प्रण तिरंगा थामने की इच्छा शक्ति की साथ अक्षत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी परिक्षा के शामिल हुआ और इस परीक्षा ना केवल देश में 30 वा स्थान हासिल किया बल्कि सर्विस सलेक्शन बोर्ड में पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक अंक हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम गौरांवित किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी की प्रवेश परिक्षा केवल एक प्रवेश परीक्षा नहीं है बल्कि साहस, अनुशासन और देशसेवा के सपने को हकीकत में बदलने की पहली कसौटी है। देश के लाखों युवा हर साल इस परीक्षा के फॉर्म भरते हैं, लेकिन अक्षत जैसे कुछ विरले ऐसा जज्बा रखते हैं कि लिखित परीक्षा के कठिन प्रश्नों से लेकर एसएसबी के 5 दिनों तक चलने वाले मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सामना करते हुए अहम स्थान हासिल करते है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में यातायात नियमों का पालन करें या जुर्माना के लिए तैयार रहें

ट्रैफिक उल्लंघन पर लगभग 177 प्रकरण और 2 लाख 23 हजार का जुर्माना वसूल

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़े किये वाहनों, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर विगत 28 मार्च से 18 अप्रैल तक यातायात दल द्वारा लगातार मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई जिसमें लगभग 177 प्रकरण दर्ज कर 2 लाख 23 हजार 900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्य में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक जितेन्द्र चन्द्रा, उप निरीक्षक समेलाल सोनवानी, प्रधान आरक्षक श्याम प्रधान, मुकेश साहू, आरक्षक अक्षय रात्रे और सनसाई तिग्गा आदि शामिल थे।

दल के कार्य से साबित हो रहा है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में यातायात नियमों का पालन करें या जुर्माना के लिए तैयार रहें।

पोषण पखवाड़ा में कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने पालकों से बच्चों के मोबाइल लत को दूर करने की अपील

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण पखवाड़ा (9 से 23 अप्रैल) पर जिले के नागरिकों से अपील किया है कि बच्चों और माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पौष्टीक खानपान पर ध्यान दिया जाए वहीं बच्चों के द्वारा बहुत ज्यादा समय तक मोबाइल में गेम खेलने, यूट्यूब और फेसबुक में वीडियो, शॉर्ट्स को देखने की आदत (लत) को कम करने के लिए पालकों को प्रभावी कदम उठाने की अपील की है ताकि जिले में बच्चे और माता स्वस्थ हो और कुपोषण मुक्त हो।

सुरक्षा के साथ संवेदनाः सुदूर माड़ के गांवों में पहुंची कांकेर पुलिस, ग्रामीणों का जीता भरोसा

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर / :- कांकेर पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कांकेर पुलिस द्वारा एक बेहद सराहनीय पहल की गई है।पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा (भा.पु.से.) के कुशल नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम नारायणपुर सीमा से लगे सुदूर माड़ क्षेत्र के अत्यंत दुर्गम गांवों-डोमांज, मुतनतोड़ा, उकाट, बड़ेकोट और गेड़ाबेड़ा पहुंची। यहां आयोजित विशेष 'सिविक एक्शन कार्यक्रम' के माध्यम से पुलिस ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि सेवा और सुरक्षा का एक नया उदाहरण भी पेश किया। जनहितकारी योजनाओं से कराया अवगत शिविर के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ सीधा और आत्मीय संवाद स्थापित किया।

पुलिस ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं, जैसे महतारी वंदन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को शीघ्र मिले, इसके लिए पुलिस विभाग संबंधित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा। राहत सामग्री का वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता इस अभियान के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे साड़ी, धोती, चप्पल, गमछा, टी-शर्ट, कंबल और राशन सामग्री वितरित कर राहत प्रदान की गई। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करते हुए गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उन्हें नियमित स्कूल भेजने और आंगनबाड़ियों की सुविधाओं का लाभ लेने पर भी विशेष जोर दिया गया। शांति और विकास की अपील कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में शांति, भाईचारा और विकास की गति को तेज करने के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर भटके हुए युवाओं और माओवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा में लौटने, आत्मसमर्पण करने और एक सामान्य व सम्मानजनक जीवन अपनाने का कड़ा संदेश भी दिया गया। इनकी रही प्रमुख उपस्थिति

इस पूरे अभियान को सफल बनाने में निरीक्षक निर्मल जांगड़े (थाना प्रभारी कोयलीबेड़ा), निरीक्षक मनीष नेताम (छत्तीसगढ़ प्रतापपुर टीम), उप निरीक्षक विजय कुलदीप, सहायक उप निरीक्षक सम्पत टांडिया (छत्तीसगढ़ इंडिगो टीम पखांजूर) और छत्तीसगढ़ के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांकेर पुलिस की इस पहल ने सुदूर अंचलों में 'सुरक्षा, सेवा और विश्वास' के अपने संकल्प को एक बार फिर चरितार्थ किया है।

सारंगढ़ में पत्रकार-अधिवक्ता से मारपीट मामलाः संपादक पी.एल. कुर्रे ने की कड़ी निंदा, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सरसींवा/सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में पत्रकार और अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सृजन भूमि छत्तीसगढ़ दैनिक अखबार एवं न्यूज़ के चीफ एडिटर पी. एल. कुर्रे (प्रीतलाल कुर्रे) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।बताया जा रहा है कि एक अधिवक्ता अपनी माता के लंबित पीएम किसान सम्मान निधि प्रकरण को लेकर कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ एक पत्रकार भी मौजूद थे। प्रक्रिया के तहत उन्हें जिला कृषि अधिकारी से कृषि विस्तार अधिकारी के पास भेजा गया, जहां आरोप है कि कृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल का व्यवहार अचानक उग्र हो गया और कथित रूप से मारपीट की घटना हुई।घटना का एक गंभीर पहलू यह भी बताया जा रहा है कि उपसंचालक कृषि की मौजूदगी में पीड़ितों को कार्यालय से बाहर जाने से रोका गया। मामले का सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद 24 घंटे बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आरोपी अधिकारी को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।इधर, पत्रकार महाकल्याण संघ, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने भी घटना की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि–दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई

निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं हुई पीड़ितों को सुरक्षा नहीं मिली

तो प्रदेशभर के पत्रकार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। संपादक पी.एल. कुर्रे ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ÷कलम को दबाने की हर कोशिश का जवाब मजबूती से दिया जाएगा।÷ अब बड़ा सवालः क्या जिले में कानून का राज कायम रहेगा या अफसरशाही हावी होगी?

महिला कर्मचारी से 5000 की वसूली ने खोली पोल

बिल पास कराना है तो 20% दो! घरघोड़ा उपकोषालय बना 'रिश्वतखोरी का अड्डा'

रायगढ़/मूक पत्रिका

घरघोड़ा जिले में भ्रष्टाचार अब खुलेआम नाच रहा हैज और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदकर बैठे हैं! घरघोड़ा उपकोषालय से सामने आया ताजा मामला न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे ÷सेवा÷ के नाम पर जनता और कर्मचारियों को लूटा जा रहा है।

आरोप है कि उपकोषालय अधिकारी मुकेश नायक ने चिकित्सा बिल पास करने के बदले महिला कर्मचारी से खुलेआम रिश्वत मांगी – और आखिरकार 5000 रुपये वसूल भी लिए!

÷राशि चाहिए तो हिस्सा देना पड़ेगा÷ – खुलेआम धमकी

शिकायतकर्ता राजेश कुमार पटनायक ने बताया कि उनकी पत्नी, सिम्मी पटनायक (सहायक ग्रेड-03) ने डिलीवरी (सिजेरियन) के बाद 44,425 रुपये का मेडिकल क्लेम जमा किया था।

लेकिन उपकोषालय में बैठे अधिकारी ने साफ शब्दों में फरमान सुना दिया–

÷बिल पास कराना है तो 20त्न देना पड़ेगा!÷

पहले 10,000 रुपये की मांग, फि र ÷राहत÷ देकर 8000 रुपये, और आखिर में दबाव बनाकर 5000 रुपये वसूल लिए गए।

WhatsApp से रिश्वत का खेल – डिजिटल सबूत मौजूद!

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि रिश्वत लेने का तरीका भी हाईटेक था–

WhatsApp पर नंबर भेजा गया

PhonePe के जरिए पैसा ट्रांसफर कराया गया

बैंक स्टेटमेंट, चैट, कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मौजूद

यानी भ्रष्टाचार अब ÷कैश÷ से निकलकर ÷ऑनलाइन ट्रांजैक्शन÷ तक पहुंच चुका है!

÷हर बिल में 20त्न फिक्स÷ – अधिकारियों में दहशत

सूत्रों की मानें तो लैलूंगा , घरगोड़ा और तमनार क्षेत्र के आहरण-संवितरण अधिकारियों के बीच यह बात आम हो चुकी है कि–

÷बिना कमीशन कोई बिल पास नहीं होता!÷

इतना ही नहीं, मृत शासकीय सेवकों के भुगतान तक रोके जा रहे हैं

महीनों तक फाइलें लटकाकर मानसिक दबाव बनाया जाता है

शिकायत मुख्यमंत्री से कलेक्टर तकज फिर भी सन्नाटा

पीड़ित परिवार ने पूरे सबूत के साथ

मुख्यमंत्री

कलेक्टर रायगढ़

तक शिकायत भेज दीज

लेकिन सबसे बड़ा सवाल–

इतनी बड़ी रिश्वतखोरी के बाद भी प्रशासन आखिर खामोश क्यों है?

जनता का फूटा गुस्सा – ÷ऐसे अफसरों को बर्खास्त करो!÷

अब क्षेत्र में आक्रोश फूट पड़ा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं–

क्या सरकारी नौकरी अब ÷उगाही का लाइसेंस÷ बन गई है?

क्या ईमानदार कर्मचारी अब सिस्टम में टिक ही नहीं सकते?

मांगः तुरंत कार्रवाई, नहीं तो आंदोलन!

शिकायतकर्ता ने साफ कहा है आरोपी अधिकारी पर कड़ी विभागीय जांच हो

सेवा समाप्ति जैसी सख्त कार्रवाई हो

पिछले सभी मामलों की जांच कर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए

यह मामला सिर्फ 5000 रुपये की रिश्वत का नहींज

यह पूरे सिस्टम में फैले ÷कट मनी कल्चर÷ का जिंदा सबूत है।

अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुईज

तो सवाल सिर्फ एक रहेगा–

÷क्या भ्रष्टाचार ही अब शासन की असली पहचान बन चुका है?÷

संक्षिप्त समाचार

न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी की पत्नी ने अपने पुराने आपत्तिजनक पोस्ट पर मांगी माफी

न्यूयॉर्क , एजेंसी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की पत्नी रामा दुवाजी ने कई वर्ष पहले किए गए अपने एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह मामला तब सामने आया जब एक कंजर्वेटिव मीडिया संस्थान ने उनकी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को खंगालकर उजागर किया। एक इंटरव्यू में दुवाजी ने कहा कि उन्हें अपने पुराने पोस्ट को लेकर गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने कहा, ' 15 साल की उम्र में उन्होंने वह पोस्ट किया था, लेकिन उम्र कोई बहाना नहीं हो सकती। मैंने जो भाषा इस्तेमाल की, वह दूसरों के लिए नुकसानदेह थी।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ीं और समझा कि मैंने उन्हें कितना आहत किया। इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं।' हालांकि, दुवाजी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किन-किन पोस्ट की बात कर रही हैं और न ही उन्होंने इस्राइल से जुड़े अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की, जिन पर भी विवाद हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पुराने पोस्ट में एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने अतीत में कुछ ऐसे पोस्ट भी शेयर किए थे जिनमें फिलिस्तीनी उग्रवादियों की प्रशंसा की गई थी। गौरतलब है कि दुवाजी को हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसे हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले का समर्थन करने वाला माना गया था।

पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन फटने से आठ की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल हैं। यह हादसा हरिपुर जिले के हत्तर इंडस्ट्रियल एस्टेट इलाके में हुआ। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार, ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक ग्राइंडिंग मिल के नजदीक पाइपलाइन में धमाका हुआ, जिससे भीषण आग लग गई। धमाके के बाद पास का एक मकान भी आग की चपेट में आ गया, जिससे नुकसान और बढ़ गया तथा राहत कार्य में मुश्किलें आईं। हरिपुर के जिला पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अब तक चार महिलाओं और छह बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस हादसे में कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग पर काबू पाने और घायलों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। हरिपुर के डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद ने बताया कि ज्यादातर मौतें दम घुटने के कारण हुई हैं।

19 को भारत आ सकते हैं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति

सियोल , एजेंसी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग 19 अप्रैल को भारत दौरे पर आ सकते हैं। कोरियाई राष्ट्रपति के सलाहकार वी सुंग-लैक के मुताबिक ली अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नई दिल्ली से करेंगे। उनकी यात्रा 19 से 21 अप्रैल तक होगी। लैक का कहना है कि यह आठ साल में किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। कोरियाई राष्ट्रपति की इस पहली यात्रा का उद्देश्य बढ़ती भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच व्यापार, रक्षा, एआई और जहाज निर्माण में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबधों को मजबूती देना है।

यूएस की धमकी- समझौते पर ही हटेगी नाकाबंदी

वॉशिंगटन/तेहरान/बीजिंग, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी लंबे समय तक जारी रखने के संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह कार्रवाई अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस नाकेबंदी का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका इसे लंबे समय तक जारी रख सकता है।

अमेरिकी नीति पर ट्रंप के बड़े बयान, ईरान से समझौते के लिए खुद जाएंगे पाक पीएम ! मोदी पर भी बोले

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 40 दिनों से अधिक की जंग के बाद तनावपूर्ण शांति के बीच आई इस टिप्पणी को उनके यू-टर्न की तरह भी पेश किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी टिप्पणी की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 'दोस्त' बताते हुए कहा, मोदी के साथ फोन पर उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी' रही। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के फोन कॉल की पुष्टि की थी। गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को सकारात्मक बताया। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा है कि

अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और ईरान से इतर इस्राइल और लेबनान के बीच युद्धविराम पर भी बयान दिया। उन्होंने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 10वां युद्ध रोकने में सफलता हासिल की है। डोनरो सिद्धांत जुमले का इस्तेमाल ट्रंप की 2026 की विदेश नीति के संदर्भ में किया जाता है। इस धारा के तहत सरकार 'अमेरिका सबसे पहले और केवल अमेरिका' जैसे रुख पर जोर देती है। डोनरो सिद्धांत पूर्व राष्ट्रपति के दौर में इस्तेमाल 'मोनरो सिद्धांत' से प्रेरित है। दरअसल, 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने यूरोपीय उपनिवेशीकरण बंद करने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में किसी भी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी बढ़ाने जैसे कृत्य के रूप में देखा जाएगा। बीते करीब 200 साल से अधिक समय से इस नीति को डोनरो सिद्धांत की तरह पेश किया जा रहा है। अब गाहे-ब-गाहे ट्रंप की नीतियों को भी इसी जुमले के आधार पर पेश किया जाता है। वहीं ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ बहुत जल्द जीत का दावा किया। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं में भारी गिरावट का उल्लेख किया। उसकी नौसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। ट्रंप ने ईरानी कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने सुलेमानी को 'सबसे बुरे आतंकवादियों में से एक' बताया, उस पर अमेरिकी सैनिकों पर हमलों का आरोप लगाया।

ट्रंप फिर दे सकते हैं कैमरन हैमिल्टन को एफईएमए की कमान, पहले कर चुके हैं बर्खास्त

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी नेवी सील कैमरन हैमिल्टन को फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का स्थायी प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं, जो कि एक चौकाने वाला घटनाक्रम है। क्योंकि पिछले साल ही ट्रंप प्रशासन ने उन्हें इस पद से हटा दिया था। हैमिल्टन पूर्व अमेरिकी नेवी सील रह चुके हैं। हैमिल्टन पिछले साल जनवरी से मई तक फेमा के अंतरिम प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें कैपिटल हिल में यह गवाही देने के एक दिन बाद उन्हें निकाल दिया गया कि वह उस ऑर्गनाइजेशन को खत्म करने के प्रपोजल से सहमत नहीं हैं। ट्रंप ने बार-बार इस एजेंसी को भंग करने का विचार रखा था। हैमिल्टन ने सदन की एक समिति के सामने साफ कहा था कि फेमा को खत्म करना अमेरिकी जनता के हित में नहीं होगा। इस बयान के अगले ही दिन उन्हें पद से हटा दिया गया था। फेमा अमेरिका में आपदाओं के समय राहत कार्यों का तालमेल बिठाने वाली मुख्य एजेंसी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक इस एजेंसी का कोई स्थायी प्रमुख नहीं रहा है। फिलहाल यह एजेंसी अपने तीसरे अस्थायी नेता के भरोसे चल रही है। जानकारों का कहना है कि स्थायी नेतृत्व न होने से एजेंसी की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने बुधवार को हैमिल्टन को इस पद का प्रस्ताव दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इस खबर की जानकारी सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी।

भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में आईसीई ने हिरासत में लिया

क्रिमिनल जैसा बर्ताव; अमेरिकी सेना में है बेटा

टेक्सास , एजेंसी। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल की 53 वर्षीय महिला मीनू बत्रा को इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। मीनू बत्रा का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें 24 घंटे तक बिना खाना-पानी के रखा गया और कई दिनों तक दवाइयां भी नहीं दी गईं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा बर्ताव किया गया जबकि वे 35 सालों से अमेरिका में रह रही हैं। वहीं मीनू बत्रा का बेटा अमेरिकी सेना का हिस्सा है।

जानकारी के मुताबिक मीनू बत्रा को 17 मार्च को हार्लिजेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह काम के सिलसिले में मिलवॉकी जा रही थीं। फिलहाल वह रेमंडविल के एल वैले डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। उन्होंने अदालत में दाखिल याचिका में यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें हथकड़ी लगाकर फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया।

अपने बयान में मीनू बत्रा ने बताया कि सुरक्षा जांच के बाद कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोका और उनकी इमिग्रेशन स्थिति के बारे में पूछा। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ डिपोर्टेशन का आदेश है। हालांकि बत्रा ने कहा है कि उनके पास 'विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल' के तहत वैध काम करने की अनुमति है, जो उन्हें साल 2000 में मिली थी। मीनू बत्रा ने बताया कि एक अधिकारी ने उनसे कहा, 'इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहां हमेशा रह सकती हैं।' इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मीनू बत्रा का

आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद उनसे हाथ पीछे करके फोटो खिंचवाए गए ताकि ऐसा लगे कि वह हथकड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया के लिए ली गईं। उन्होंने कहा, 'इससे मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ और मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया।' हिरासत के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कुछ ही दिनों में उनकी आवाज भी चली गई।

मीनू बत्रा का अतीत भी काफी मुश्किलों भरा रहा है। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में भारत में सिख विरोधी हिंसा के दौरान उनके माता-पिता की हत्या हो गई थी, जिसके बाद वह अमेरिका चली गई थीं। वह पिछले 35 साल से अमेरिका में रह रही हैं और टेक्सास में हिंदी, पंजाबी और उर्दू की एकमात्र लाइसेंस प्राप्त कोर्ट इंटरप्रेटर हैं। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक इमिग्रेशन कोर्ट में काम किया है। मीनू बत्रा के चार बच्चे भी हैं। उनका एक बेटा हाल ही में अमेरिकी सेना में शामिल हुआ है और उसने अपनी मां की रिहाई के लिए अपील की है। उनके बेटे ने एक बयान में कहा, 'मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा देश मेरी मां को वापस दिला दे।' तीसरे देश में भेजे जाने की संभावना मीनू बत्रा के वकीलों का कहना है कि उनकी हिरासत कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है और वे उनकी रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। वहीं अमेरिकी सरकार की ओर से कहा गया है कि मीनू बत्रा के खिलाफ साल 2000 में ही डिपोर्टेशन का अंतिम आदेश जारी हो चुका है।

गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वह तब तक हिरासत में रहेंगी जब तक उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और उन्हें पूरा कानूनी अधिकार दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि काम करने की अनुमति किसी को अमेरिका में रहने का स्थायी अधिकार नहीं देती। उनकी कानूनी स्थिति के अनुसार उन्हें भारत भेजा नहीं जा सकता, लेकिन किसी तीसरे देश में भेजा जा सकता है। मीनू बत्रा के वकील दीपक अहलूवालिया ने कहा है कि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि उन्हें कहां भेजा जाएगा।

साढ़े तीन लाख हैती प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक

ट्रंप प्रशासन को झटका, प्रतिनिधि सभा ने पारित किया हैती प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा बिल

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को एक ऐसा विधेयक पारित किया, जिसमें दोनों प्रमुख दलों के सांसदों ने मिलकर वोट किया। यह विधेयक हैती के

प्रवासियों को मिलने वाली अस्थायी सुरक्षा को बढ़ाने से जुड़ा है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के उस प्रयास के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें इस सुरक्षा कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी।

विधेयक को डेमोक्रेट सांसदों ने कुछ रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से आगे बढ़ाया। जबकि, रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व इसका विरोध कर रहा था। इसमें ट्रंप प्रशासन से मांग की गई है कि हैती के प्रवासियों को मिलने वाली अस्थायी सुरक्षा को तीन साल के लिए बढ़ाया जाए। इससे अमेरिका में रह रहे लाखों योग्य प्रवासी देश से निकाले जाने (निर्वासन) के डर के बिना रह सकेंगे।

मतदान में 224 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया और 204 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सदन में तालियां भी बजीं। यह विधेयक अब सीनेट में जाएगा और यह भी संभावना है कि राष्ट्रपति इसे रोकने के लिए वीटो कर दें। डेमोक्रेट सांसद अयाना प्रेसली ने कहा, मैं जानती हूं कि हैती से आए हुए हमारे पड़ोसी हमारे समुदायों, हमारी संस्कृति, हमारे काम और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम हैं। उन्होंने बताया कि हैती के प्रवासी स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे समस्या नहीं हैं, बल्कि समाधान का हिस्सा हैं। प्रेसली ने कहा कि हैती के लोगों को वापस भेजना उनके लिए 'मृत्युदंड' जैसा होगा, क्योंकि वहां प्राकृतिक आपदाएं और गिरोहों की हिंसा की गंभीर स्थिति है। यह विधेयक अमेरिका में रह रहे लगभग 3.5 लाख हैती प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि प्रशासन कई समूहों का यह दर्जा खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अगले दो हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले पर विचार करेगा।

इज़रायल में मधुमक्खियों का आतंक... तेल अवीव में लगा 'लॉकडाउन'

तेल अवीव, एजेंसी। इज़रायल के तेल अवीव और आसपास के कई शहरों में अचानक हजारों मधुमक्खियों का बड़ा झुंड देखने को मिला। जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि स्थानीय प्रशासन को तुरंत अलर्ट जारी करना पड़ा और कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से दुकानों, कैफे और शॉपिंग सेंटर को बंद कर दिया जिसके बाद अस्थायी लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिली।बता दें कि इजरायल में इन दिनों मधुमक्खियों का भयानक हमला देखा जा रहा है। तेल अवीव समेत कई शहरों में मधुमक्खियों के झुंड आसमान में छा गए। इतनी ज्यादा मधुमक्खियां हैं कि अधिकारियों को आपातकालीन चेतावनी जारी करनी पड़ी है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और मधुमक्खियों को किसी भी तरह से परेशान या नुकसान न पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि मधुमक्खियों का विशाल झुंड इमारतों, गाड़ियों और बाजारों के आसपास मंडरा रहा है, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई और पूरे शहर में अफता-तफरी मच गई।स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी टीमें और ट्रेनड मधुमक्खी पालकों को मौके पर भेजा गया। इन टीमों ने मधुमक्खियों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम शुरू किया।विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई हमला नहीं बल्कि मधुमक्खियों की प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जिसे स्वार्मिंग कहा जाता है। इसमें मधुमक्खियों का एक बड़ा समूह अपनी पुरानी कॉलोनी छोड़कर नई रानी के साथ नया घर खोजने निकलता है। यह प्रक्रिया अक्सर तब होती है जब छत्ते में जगह कम हो जाती है या पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलती हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मौसम में बदलाव, फूलों की कमी या छत्ते के टूटने जैसी वजहें इस तरह के बड़े झुंड का कारण बन सकती हैं। हालांकि घटना से किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं ।

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे भारत

लश्कर-ए-तैयबा से हैं संबंध', इस्राली विदेश मंत्री का दावा

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि यरूशलम और नई दिल्ली के बीज संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। गिदोन सार ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने एक वैश्विक प्रतिनिधिमंडल के साथ जानकारी साझा की। सार ने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया भर से आए सम्मानित हिंदू नेताओं के एक समूह को जानकारी देने का अवसर मिला। इस बातचीत में उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और इस्राइल से जुड़े संघर्ष की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस्राइल पिछले ढाई साल से इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ एक गंभीर युद्ध लड़ रहा है, जिसका लक्ष्य इस्राइल को खत्म करना है। उन्होंने इसे एक 'बहुत बड़ा खतरा' बताया। सार ने यह भी कहा कि इस्राइल ने कई मोर्चों पर बढ़त हासिल की है और उसने इस्लामी चरमपंथ के 'आतंकी नेटवर्क' को काफी कमजोर किया है, जिसका नेतृत्व ईरान करता है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का असर पश्चिम एशिया से बाहर भी देखने को मिलेगा। भारत के साथ सुरक्षा सहयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास के संबंध अन्य चरमपंथी संगठनों से हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) भी शामिल है। इस्राइली विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह के संगठनों के बीच वैश्विक स्तर पर जुड़ाव है और ये मिलकर काम करते हैं। इस्राइल पहले ही लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है और वह चाहता है कि भारत भी हमास को उसी तरह सूचीबद्ध करे। इस्राइल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार इन नेटवर्क और उनके संबंधों के बारे में जानकारी रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के आईआरजीसी, हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की मदद से हमले करते हैं। अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर ईरानी एजेंट सीधे यूरोप में हमला नहीं करते, बल्कि वे किसी स्थानीय आपराधिक समूह के जरिये हमला करवाते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर भारत सिर्फ यह घोषणा भी करता है, तो इसका वैश्विक स्तर पर बड़ा असर होगा, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश भारत के रुख को देखते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि भारत की जमीन पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दक्षिणी लेबनान में 10 किमी का सुरक्षा जोन बनाए रखेगा इस्राइल

यरूशलम, एजेंसी। ईरान के मुद्दे पर नेतन्याहू ने दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे समुद्री नाकेबंदी जारी रखेंगे और ईरान की बची हुई परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। नेतन्याहू ने इन कदमों को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे आने वाले वर्षों में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला के साथ युद्धविराम लागू होने के बाद भी इस्राइल दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की। यह समझौता नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच हुआ है और इसे अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार शाम 5 बजे से लागू किया जाना है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्ला की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें इस्राइली सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पीछे हटने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्राइली सेना लेबनान के अंदर बनाए गए इस सुरक्षा क्षेत्र में ही तैनात रहेगी। उनका कहना है कि यह सुरक्षा क्षेत्र उत्तरी इस्राइल के इलाकों को हमलों और टैंक रोधी हथियारों से बचाने में मदद करेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का मौका है। उन्होंने बताया कि ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें और लेबनान के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। नेतन्याहू के अनुसार, यह मौका इसलिए बना है क्योंकि इस्राइल ने लेबनान में ताकत का संतुलन अपने पक्ष में बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक महीने में लेबनान की ओर से सीधे शांति वार्ता के संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि इन बातचीतों में इस्राइल की दो मुख्य शर्तें होंगी- पहली, हिजबुल्ला को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे, और दूसरी, एक स्थायी शांति समझौता होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (आईआरसी) ने इस्राइल-लेबनान युद्धविराम की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे 'उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित राहत' बताया है, जिन्होंने हफ्तों तक लगातार हिंसा झेली है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि लेबनान में 2,100 से अधिक लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं और दस लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। संगठन ने बयान में कहा, 'इस युद्धविराम का उपयोग नागरिकों की सुरक्षा, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और स्थायी शांति की नींव

रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में किया जाना चाहिए।' संगठन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसे राजनीतिक मार्ग पर चलने का आग्रह किया जो आगे और जानमाल के नुकसान को रोके और संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के साथ युद्धविराम को लेकर आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर से बात की। दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की ताकि वाणिज्यिक जहाज जलडमरूमध्य से स्वतंत्र रूप से गुजर सकें और ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक बाजारों तक पहुंच सके। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। अमेरिका की तरफ से इस्राइल-लेबनान में युद्धविराम के बाद शांति वार्ता की मेजबानी के प्रस्ताव पर कई गुटों में मतभेद है। कुछ लोग इसे वार्ता की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं, जिससे पिछले छह हफ्तों के युद्ध से तबाह हुए देश में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन कई अन्य लोग, ठीक इसी कारण से, इसे बेहद चिंताजनक मानते हैं - यह विचार कि उनके राष्ट्रपति इजरायल के साथ बातचीत करने के लिए बैठेंगे। और यह 10 दिवसीय युद्धविराम वास्तव में इसके संभव होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लेबनानी संसद के बेहद प्रभावशाली अध्यक्ष नबीह बेरी की एक प्रमुख शर्त थी। वह देश के सबसे वरिष्ठ शिया राजनेता हैं, और उन्होंने लंबे समय से यह कहा था कि गोलीबारी के बीच कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसलिए, इस 10 दिवसीय युद्धविराम ने संभावित रूप से इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। इस युद्धविराम की घोषणा के बाद उन्होंने कहा है कि लेबनानी क्षेत्र पर इस्राइली कब्जे की मौजूदगी लेबनानी लोगों को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

आखिरी ओवर में 15 रन बनाए, स्टब्स-राहुल की फिफ्टी; कुलदीप, एनगिडी, अक्षर को 2-2 विकेट

दिल्ली ने बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में हराया

मुंबई। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए छह विकेट से मैच अपने नाम किया। दिल्ली की टीम इस तरह दो हार के बाद जीत की राह पर लौटने में सफल रही। दिल्ली के लिए केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जीत के हीरो रहे।

दिल्ली की जीत

केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के अर्धशतकों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को छह विकेट से हराया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 175 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली ने चार विकेट पर 179 रन बनाकर मैच जीत लिया। दिल्ली के लिए राहुल और स्टब्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर मैच फिनिश किया। स्टब्स ने 47 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए, जबकि राहुल 34 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों के सहारे 57 रन बनाकर आउट हुए। मिलर ने 10 गेंदों पर एक चौका और दो छक्कों की मदद से 22 रनों की नाबाद पारी खेली। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए, जबकि क्रुणाल पांड्या को एक सफलता मिली।

अक्षर रिटायर्ड हर्ट हुए

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। अक्षर और स्टब्स के बीच पांचवें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन उन्हें खिंचाव आ गया जिस कारण वह मैदान से बाहर चले गए। अक्षर 19 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे।

स्टब्स-अक्षर की साझेदारी

ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल के बीच पांचवें विकेट के लिए साझेदारी पनप रही है। दिल्ली का स्कोर 120 रन के पार पहुंच गया है। आरसीबी को अब तक चार सफलताएं मिली है।

केएल राहुल आउट

क्रुणाल पांड्या ने केएल राहुल को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका दिया है। राहुल 34 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। राहुल और स्टब्स के बीच 69 रनों की साझेदारी हुई।

स्टब्स का पचासा

ट्रिस्टन स्टब्स ने आरसीबी के खिलाफ अर्धशतक जड़ दिया है। दिल्ली का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया है। अक्षर के रिटायर्ड होकर पवेलियन लौटने के बाद स्टब्स का साथ डेविड मिलर निभा रहे हैं।

सॉल्ट का अर्धशतक काम ना आया

पहले बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु के लिए फिल सॉल्ट ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 38 बॉल पर 63 रन बनाए। उनकी इस सीजन की यह दूसरी फिफ्टी रही। उनके और विराट कोहली के बीच पहले विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी हुई। सॉल्ट के अलावा टिम डेविड ने 26, कोहली ने 19 और देवदत्त पडिक्कल ने 18 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए

ब्रीफ न्यूज

केकेआर के लिए गहराता संकट, रॉयल्स की वापसी की उम्मीद

नई दिल्ली । कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छह मैचों के बाद भी एक भी जीत दर्ज न कर पाने वाली केकेआर को अब अपनी पिछली हार के 48 घंटे से भी कम समय में ऊर्जावान राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से भिड़ना है। केकेआर का अभियान कई मोर्चों पर पटरी से उतर गया है। सीजन शुरू होने से पहले ही मुख्य तेज गेंदबाज हर्षित राणा और आकाश दीप चोट के कारण बाहर हो गए थे। मथीशा पथिराना के आने में देरी और अनिश्चितता ने संकट को और गहरा कर दिया है। कैमरून ग्रीन के गेंद के साथ केवल कभी-कभार ही योगदान देने के कारण, केकेआर के पास अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण है, जिसमें मारक क्षमता और धार दोनों की कमी साफ दिखती है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि वे इस सीजन में सांख्यिकीय रूप से सबसे खराब तेज गेंदबाजी टीमों में से एक रहे हैं। गुजरात टाइटंस (जीटी) से मिली हार के बाद अजिंक्य रहाणे ने बेबाकी से कहा, जो खिलाड़ी पावरप्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, वे अनुभवहीन हैं। जब यह अनुभवहीन आक्रमण टूर्नामेंट की सबसे विनाशकारी सलामी जोड़ी के सामने आता है, तो केकेआर के पास योजना बनाने या कल्पना करने के लिए ज्यादा समय नहीं है।

आईपीएल में आज अजेय पंजाब किंग्स के सामने पंत की लखनऊ सुपर जाइंट्स

नई दिल्ली। रविवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस सीजन में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है और टीम ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है, जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। कप्तान ऋषभ पंत की चोट ने लखनऊ की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है, जिससे यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहाँ टीम ने अपने शुरुआती मैचों में शानदार खेल दिखाते हुए अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है।

हैदराबाद ने चेन्नई को 10 रन से हराया

ईशान मलिंगा ने झटके तीन विकेट

हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।

हैदराबाद ने चेन्नई को हराया

सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।

चेन्नई को सातवां झटका

चेन्नई को सातवां झटका साकिब हुसैन ने दिया। उन्होंने शिवम दुबे को बोल्ड किया। वह 21 रन बनाकर लौटे। अब जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज क्रीज पर हैं।

चेन्नई को छठा झटका

चेन्नई को छठा झटका ईशान मलिंगा ने दिया। उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच कराया। वह 30 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब शिवम दुबे का साथ देने जेमी ओवरटन आए हैं।

पांचवां विकेट गिरा

चेन्नई को पांचवां झटका शिवांग कुमार ने दिया। उन्होंने लिविंगस्टोन के हाथों डेवाल्ड ब्रेविस को कैच कराया। वह खाता भी नहीं खोल पाए। अब शिवम दुबे आए हैं।

अभिषेक-क्लासन की फिफ्टी हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और हेनिरक क्लासन ने 59-59 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। छ्ब्ल्यू से जैमी ओवर्टन और अंशुल कम्बोज ने 3-3 विकेट लिए।

ईशान मलिंगा ने 3 विकेट झटके हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने 3 विकेट झटके। उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान और ऋतुराज गायकवाड को भी पवेलियन भेजा। नीतीश कुमार रेड्?डी और प्रफुल्ल हिंगे ने 2-2 विकेट झटके। शिवांग कुमार और साकिब हुसैन को एक-एक विकेट मिला।

अमेरिका में लोकेश सत्यनाथन ने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता

8.21 मीटर छलांग लगाई, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन डिवीजन-आई खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय भारतीय लॉन्ग जंपर लोकेश सत्यनाथन ने अमेरिका के अर्कासस में आयोजित (नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन) डिवीजन-ढ्ढ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। लोकेश ने 8.21 मीटर की छलांग लगाकर न केवल अपना पिछला इंडोर नेशनल रिकॉर्ड (8.01 मीटर) तोड़ा, बल्कि वे यह खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। हादसे में चेहरे पर आई थीं गंभीर चोटें, फिर भी नहीं हारी हिम्मत लोकेश की यह कामयाबी आसान नहीं थी। साल 2022 में अमेरिका जाने से पहले बेंगलुरु में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। चोटों, दर्द और करियर में आए उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने अपने पिता की ताकत और मां के विश्वास के दम पर मैदान पर वापसी की।

ऑल टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचे

इस शानदार जीत के साथ लोकेश सत्यनाथन अब भारत के ऑल टाइम लॉन्ग जंपर्स की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे अब केवल जेस्विन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर जैसे स्थापित नाम ही हैं।

बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ऑस्कर शिमट का निधन

ब्राजील। बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक स्कोर करने वालों में से एक ब्राजील के ऑस्कर शिमट का देहांत हो गया है। वे 68 वर्ष के थे। शिमट ने मस्तिष्क ट्यूमर से लंबी लड़ाई के बाद कल अंतिम सांस ली। ब्राजील और यूरोप में 30 साल के पेशेवर करियर के बाद शिमट ने 2003 में संन्यास ले लिया था। 2013 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। शिमट ने पांच ओलंपिक खेलों और चार विश्व कप में ब्राजील का प्रतिनिधित्व किया और दोनों प्रतियोगिताओं में सर्वकालिक स्कोरिंग रिकॉर्ड अपने नाम किया। तीन दशक के पेशेवर करियर के बाद उन्होंने 2003 में 45 वर्ष की आयु में खेल से संन्यास ले लिया। क्लब और देश के लिए शिमट का 49 हजार 737 अंकों का अनौपचारिक विश्व रिकॉर्ड 2024 में लेब्रॉन जेम्स ने तोड़ा।

ईवुड पार्क, ब्लैकबर्न, ब्रिटेन में ब्लैकबर्न रोवर्स बनाम कोवेंट्री सिटी फुटबॉल - चैंपियनशिप के दौरान कोवेंट्री सिटी के बॉबी थॉमस ने टीम का पहला गोल किया।

डरबन टी-20 में 159 का टारगेट 5 बॉल रहते चेज किया; सीरीज में 1-0 की बढ़त

साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया

डरबन। साउथ अफ्रीका महिला टीम ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है। डरबन में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए थे, जिसे साउथ अफ्रीका ने कप्तान लौरा वोल्वार्ट की 51 रनों की पारी के दम पर आसानी से हासिल कर लिया। यह साउथ अफ्रीका का टी-20 इंटरनेशनल में अब तक का पांचवां सबसे सफल रन चेज है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

आखिरी 5 ओवर में भारत के 4 विकेट गिरे

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही थी। जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 51 गेंदों पर 71 रनों की साझेदारी की। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 119 रन था और लग रहा था कि टीम 180 के पार जाएगी। हालांकि, आखिरी 5 ओवरों में टीम इंडिया ने सिर्फ 33 रन जोड़े और 4 विकेट गंवा दिए, जिससे टीम 160 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी।

शेफाली वर्मा की तेज शुरुआत, शॉर्ट बॉल पर हुई आउट

भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और 17 गेंदों पर 34 रन बनाए । उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। हालांकि, साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर फंसाने की रणनीति अपनाई। खाका की शॉर्ट बॉल पर वे एक बार बचीं, लेकिन अंत में तुमी सेखुखुने की शॉर्ट पिच गेंद पर कैच थमा बैठीं। वहीं स्मृति मंधाना सिर्फ 7 रन बनाकर खाका का शिकार बनीं।

अयाबोंगा खाका ने 16 रन देकर लिए 3 विकेट लिए

साउथ अफ्रीका की जीत की नींव गेंदबाज अयाबोंगा खाका ने रखी। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में केवल 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

खाका इस साल फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी हुई हैं। उनके अलावा तुमी सेखुखुने ने भी दो सफलताएं हासिल कीं।

वोल्वार्ट ने एनरी डेर्कसेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की। डेर्कसेन ने 34 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अंत में क्लो ट्रायोन ने विजयी छक्का लगाकर टीम को सीरीज में 1-0 से बढ़त दिलाई।

वोल्वाईट की कप्तानी पारी, डेर्कसेन ने मैच फिनिश किया

लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत शानदार रही। ओपनिंग पर लौटीं कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 39 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में ऑन-साइड पर शानदार खेल दिखाते हुए 35 रन बटोरे।

खराब फील्डिंग और एक्स्ट्रा रनों ने बिगाड़ा भारत का खेल

भारतीय टीम की हार की एक बड़ी वजह खराब फील्डिंग और एक्स्ट्रा रन रहे। भारतीय बॉलर्स ने मैच में 14 वाइड गेंदें फेंकी, जो टी-20 में भारत का दूसरा सबसे खराब रिकॉर्ड है।इसके अलावा मैच के आखिरी ओवरों में रेणुका सिंह और सबस्टीट्यूट फील्डर अनुष्का शर्मा ने कैच छोड़े। स्लो ओवर रेट की वजह से आखिरी ओवर में भारत को सर्कल के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर रखना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर क्लो ट्रायोन ने छक्का मारकर मैच जिता दिया।

उत्पादन किया फिर धान बेचा उसी जमीन पर 'सफेद ज़हर' का हमला: सारडा एनर्जी के फ्लाई ऐश डंपिंग से उठे बड़े सवाल

रायगढ़ /मूक पत्रिका

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक अंतर्गत टेड़ा नावपारा में कृषि भूमि पर फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन और पर्यावरण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जमीन पर कुछ ही महीनों पहले धान की फ़सल लहलहा रही थी, आज उसी खेत को औद्योगिक कचरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, स्थानीय किसान सनत कुमार राठिया की भूमि, जो हाल ही में फ़सल उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई थी, अब शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स बिंजकोट द्वारा फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए प्रयोग की जा रही है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसान ने स्वेच्छा से अपनी उपजाऊ जमीन को डंपिंग के लिए दिया है या उस पर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया है।गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पर्यावरण विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे। विपक्ष के विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया था कि विभाग न तो सही जानकारी दे रहा है और न ही प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया था कि कृषि एवं वन भूमि पर फ्लाई ऐश डंपिंग नियमों के विरुद्ध है और इसे किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद घरघोड़ा क्षेत्र में हो रही डंपिंग गतिविधियां सरकारी दावों के विपरीत नजर आ रही हैं। नियमानुसार फ्लाई ऐश का निपटान केवल निर्धारित लो-लाइंग क्षेत्रों या खदानों में किया जाना चाहिए, लेकिन यहां उपजाऊ खेतों में इसका उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लाई ऐश में मौजूद भारी धातुएं मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाती हैं और भूजल को भी प्रदूषित कर सकती हैं, जिससे लंबे समय में कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित भूमि का निरीक्षण किया गया है या नहीं, और यदि यह कृषि भूमि है तो डंपिंग की अनुमति किस आधार पर दी गई। यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र की उपजाऊ भूमि बंजर में तब्दील हो सकती है और किसानों की आजीविका पर गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कि पुरे मामले में जिला प्रशासन और सम्बंधित विभाग स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाई करता है या फिर आँख मुंद कर किसानों का बदहाली का पूरा खेल तमाशा देखते रहेगा।

बारात में बाजा बजाने को लेकर विवाद, मारपीट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। थाना मुलमुला क्षेत्र के ग्राम पौना में बारात के दौरान बाजा बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में कई बाराती घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुलमुला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 अप्रैल को ग्राम खोखरा निवासी देवराज बरेठ बारात के साथ ग्राम पौना पहुंचे थे। बाराती स्कूल पारा के पास बाजा बजाते हुए नाच-गाना कर रहे थे, इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बाजा बंद करने को लेकर गाली-गलौच शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने बारातियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे मनेश्वर यादव सहित अन्य लोगों पर भी आरोपियों ने सामूहिक रूप से हमला कर दिया। इस दौरान प्रार्थी के सिर पर प्राणघातक हमला किया गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। मारपीट में धनंजय यादव की आंख में गंभीर चोट आई, जिन्हें पहले जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया।घटना की सूचना मिलते ही थाना मुलमुला पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों में नरेन्द्र उर्फ लालू नंगरा कश्यप (24), सरोज कश्यप (20), विमल कश्यप (22) एवं संजय कश्यप (27) शामिल हैं, जो सभी ग्राम पौना, थाना मुलमुला के निवासी हैं।

जगदलपुर में 'फिट बस्तर-हिट बस्तर' अभियान के तहत 21 दिवसीय योग शिविर का आगाज़ 21 अप्रैल को

प्रकृति की गोद में गूँजेगा योग का मंत्र

जगदलपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की जा रही है। वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बस्तर वन मंडल और पतंजलि योग संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ÷फिट बस्तर-हिट बस्तर÷ अभियान के अंतर्गत 21 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 'स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ तन और शांत मन' के मूल मंत्र को समर्पित यह विशेष आयोजन आगामी 21 अप्रैल से शहर के जनजातीय गौरव वाटिका में प्रारंभ होने जा रहा है। अगले 21 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से 07:30 बजे तक योगाभ्यास की कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जहाँ प्रतिभागी अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योग और प्राणायाम की विभिन्न विधाओं को सीखेंगे। डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता ने इस बारे में बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बस्तर के नागरिकों को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने पहल करना है बल्कि उन्हें मानसिक शांति और प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी का बोध कराना भी है। वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावमुक्त जीवन जीने के लिए योग एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है और जनजातीय गौरव वाटिका का शांत वातावरण इस अभ्यास के लिए सर्वोत्तम स्थान सिद्ध होगा। डीएफओ गुप्ता ने सभी नागरिकों और योग प्रेमियों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनकर स्वयं को सेहतमंद बनाए रखने के सजग प्रयास करें।यह योग शिविर बस्तरवासियों के लिए एक ऐसा मंच होगा जहाँ वे प्रकृति की शुद्ध वायु के बीच योग के माध्यम से अपनी जीवनशैली को सकारात्मक बना सकेंगे। स्थानीय प्रशासन को पूर्ण विश्वास है कि 21 दिनों का यह निरंतर अभ्यास बस्तर में एक नई स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाने की कवायदः ग्राम चिचोली में विशेष स्वास्थ्य शिविर संपन्न

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 18 अप्रैल 2026 को भटगाँव अंतर्गत ग्राम चिचोली में एक विशेष आयुष्मान कार्ड पंजीयन एव स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ साथ ही ग्राम हेतु कार्ययोजना बनाई गई जिसमें ग्राम में ब्लड प्रेशर ,शुगर की बीमारियों की पहचान हो उन्हें नियमित दवाइयां मिले और हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स की बीमारी से बचाया जा सके ग्राम के छोटे बच्चों जिनकी उम्र 6 माह से 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चे है उन्हें आयरन सिरप दिया जा सके इसी तरह से सभी गर्भवती माताओं की पहचान कर उनकी जांच कर सके किसी प्रकार की जटिलता होने पर काउंसलिंग करके उनके किसी अच्छे अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने की योजना बनाई जा सके महामारी नियंत्रण के लिए भी सेक्टर स्तर पर कार्ययोजना बनाई गई जिसमे संवेदनशील ,पहुंच विहीन गांव एवं बढ़ पीड़ित गांव की पहचान की गई। आयुष्मान कार्ड पंजीयन लक्ष्य के करीब, निरीक्षण में मिली सराहनाशिविर का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम चिचोली के हितग्राही दोपहर में अपनी अपनी सब्जी की बाड़ियो में गए थे तो टीम द्वारा वही पहुच कर कार्य संपादित किया साथ ही कुछ हितग्राही जम्मू गए थे जिसमें से 3 हितग्राहियो का फ़ोन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया गया इस प्रकार लगभग कुल 94त्र हितग्राहियो का पूर्ण पंजीयन हो चुका है। शेष बचे हितग्राहियों को भी जल्द ही कवर करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा-?शिविर की गुणवत्ता और प्रगति को परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम चिचोली पहुँची। इस निरीक्षण दल में मुख्य रूप से शामिल थेःडॉ एफ आर निराला :मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (छ्रस्ब्ल्ह)रोशन सचदेवः आयुष्मान भारत जिला समन्वयक

सेक्टर चिकित्सा अधिकारी

संबंधित सेक्टर के कर्मचारी एवं स्वास्थ्य कर्मी

प्रमुख कार्यक्रमों पर रहा फोकस

शिविर में न केवल आयुष्मान कार्ड बल्कि विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सैचुरेशन (पूर्णता) पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित न रहे।

÷हमारा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य विभाग की हर योजना का लाभ पात्र ग्रामीणों को उनके घर के समीप ही मिले। 94त्र आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पूर्ण होना एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे जल्द ही 100त्र तक ले जाया जाएगा।÷

– डॉ एफ आर निराला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (छ्रस्ब्ल्ह) ?इस शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी स्वास्थ्य जाँच कराने के साथ-साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

CBSE 10वीं में राजवीर सिंह ने 94.44% अंक हासिल कर बढ़ाया परिवार व स्कूल का मान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

सारंगढ़ क्षेत्र के होनहार छात्र राजवीर सिंह ने छ्रक्चस्श्व 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94.44 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। राजवीर शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। राजवीर की इस सफलता पर उनकी माता ममता राजीव सिंह, जो वर्तमान में सारंगढ़ जनपद अध्यक्ष हैं,उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि राजवीर बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और मेहनती रहा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक व्यस्तताओं के बावजूद राजवीर ने हमेशा अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे बताया कि राजवीर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और भविष्य में भी इसी तरह आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करेगा।

राजवीर सिंह की इस उपलब्धि पर जनपद परिवार सहित क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएँ दीं।

जिला सारंगढ बिलाईगढ़ में 'निक्षय निरामय' 100 दिवसीय अभियान के साथ आयुष्मान कार्ड और NCD जांच के लिए लग रहे वृहत शिविर

जगदलपुर/मूक पत्रिका

जिले को पूर्णतः स्वस्थ और क्षय (टीबी) मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (छ्रस्ब्ल्ह) डॉ. एफ आर. निराला के मार्गदर्शन में जिले में 'निक्षय निरामय 100 दिवसीय अभियान' का द्वितीय चरण वृहत रूप में जारी है।

अब इस अभियान के तहत केवल टीबी जांच ही नहीं, बल्कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन और ह्रष्ठ (गैर-संचारी रोग) जैसे बीपी, शुगर की जांच को भी शामिल कर एक 'कंबाइंड एक्शन प्लान' तैयार किया गया है।

गाँव-गाँव पहुँच रही हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन-इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक 'हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन' का उपयोग है। इसके माध्यम से जिले के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ही 'आयुष्मान आरोग्य शिविर' आयोजित कर निःशुल्क एक्स-रे जांच की जा रही है। मितानिनों द्वारा घर-घर स्क्रीनिंग कर संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है।

शिविरों में दी जा रही हैं ये सुविधाएँ: टीबी जांचः संदिग्ध मरीजों का मौके पर ही डिजिटल एक्स-रे और बलगम जांच।

आयुष्मान कार्ड पंजीयनः छूटे हुए हितग्राहियों का मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है ताकि उन्हें ?5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सके।

ह्रष्ठ स्क्रीनिंगः उच्च रक्तचाप , मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच एवं परामर्श।

पोषण सहायताः निक्षय मित्रों के माध्यम से टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण।

जारी हुआ 100 दिवसीय विस्तृत कार्ययोजना (रोस्टर)

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्ययोजना के अनुसार, आगामी दिनों में विभिन्न विकासखंडों के गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

बिलाईगढ़ ब्लॉकः

22.04.26- पुरगाव

23.04.26- छपोरा

24.04.26- सेमरडीह

25.04.26 मधईभाटा

27.04.26 गाड़ापाली

28.04.26- कोदवा

बरमकेला ब्लॉकः

29.04.26-राजपुर,

30.04.26-छैलफेरा,

02.05.26- बिजामाझा

04.05.26-पर्दियापाली

05.05.26- सेमीकोट

06.05.26 लिफ्टी

07.05.26 सल्हेहोना

08.05.26 नदीगांव

09.05.26 पोरथ

सारंगढ़ ब्लॉकः

20.04.26 महकमपुर

21.04.26 - सारंगढ उपजेल

11.05.26- बंजारी

12.05.26- गवालीनदिह

13.05.26 हरदी

14.05.26 कोतरी

15.05.26 रेगलमुंडा

16.05.26 साराडीह-प्रत्येक शिविर के लिए सेक्टर ऑफिसर और सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि गांव का एक भी पात्र व्यक्ति जांच और आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे।

छ्रस्ब्ल्ह की अपील-डॉ. एफ आर. निराला (छ्रस्ब्ल्ह) ने बताया कि, ÷हमारा उद्देश्य टीबी को जड़ से खत्म करने के साथ-साथ अंतिम छोर के व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। बुजुर्गों, कुपोषित बच्चों और श्रमिकों की विशेष जांच की जा रही है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य शिविर में पहुँचकर अपनी जांच कराएं और आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं।÷

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बदली ग्रामीण तस्वीर

शिलान्यास प्रोटोकॉल की अनदेखी पर बवाल, जनपद सदस्यों में नाराजगी

जगदलपुर/बस्तर /मूक पत्रिका

शिलान्यास कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की अनदेखी को लेकर क्षेत्रीय जनपद सदस्यों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।जनपद सदस्यों का कहना है कि यह केवल नाम छूटने का मामला नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई।

नाराज जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी इसी तरह प्रोटोकॉल की अनदेखी होती रही तो वे मजबूर होकर अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई है।स्थानीय लोगों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बदली ग्रामीण तस्वीर-इसी बीच, क्षेत्र में विकास कार्यों की एक सकारात्मक तस्वीर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही पक्की सड़कों से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले कच्चे रास्तों के कारण आवागमन में भारी दिक्कत होती थी, खासकर बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते थे। मरीजों को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल भेजना और किसानों को उपज बाजार तक पहुंचाना बेहद मुश्किल होता था।अब पक्की सड़क बनने से इन समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है। गांवों में एंबुलेंस और अन्य वाहन आसानी से पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भी सुधार हुआ है।

ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सड़क निर्माण उनके लिए बड़ी सौगात है।

इससे न सिर्फ आवागमन आसान हुआ है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।छत्तीसगढ़ शासन की विकास योजनाओं का असर अब गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाना है, जिससे हर गांव आत्मनिर्भर बन सके। ग्रामीणों के चेहरों पर दिख रही खुशी इस बात का संकेत है कि जब योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, तो उनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।